स्थापना : 1997 संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

वर्ष - 13 अंक - 312 | कल्याण (मुंबई), 1 से 15 मई 2015 | पेज-8 | मूल्य 5 रु.

केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ

देश के सभी श्रमिक संगठनों का संसद पर प्रचंड प्रदर्शन

दिल्ली : 28 अप्रैल को दिल्ली में रेलवे की दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशनों - ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) - ने रेलवे में एफडीआई और पीपीपी सहित रेलवे के निजीकरण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए संसद के समक्ष जंतर-मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया. देश के लगभग सभी मजदूर संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए. रेलवे के प्रत्येक जोन से दोनों फेडरेशनों से सम्बद्ध जोनल

संगठन एक-एक रेक लेकर इस आंदोलन में भाग लेने पहुंचे थे. अनुमान है कि सिर्फ रेलवे से ही करीब 25 से 30 हजार लोग इस आंदोलन में शामिल हुए.

राष्ट्रीय संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में करीब 10 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी दिल्ली पहुंचे थे. राष्ट्रीय संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक और ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री कॉम. शिवगोपाल मिश्रा ने बताया कि प्रदर्शन में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लाइज फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल आर्गनाइजेशन और कन्फेडरेशन ऑफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज संगठन के लाखों सदस्य कर्मचारी इस आंदोलन भाग लिया. **शेष पेज 7 पर...**

सरकारी कर्मचारियों को प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा की अनुमति नहीं

दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक आदेश निकालकर कहा है कि भारतीय रेल द्वारा चलाई जा रही ऑन ड्यूटी किसी काम से जा रहे रेलकर्मियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को 'प्रीमियम ट्रेनों' में यात्रा की अनुमति नहीं है. यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें इसका भुगतान करना होगा. उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल द्वारा डायनामिक फेयर प्राइसिंग पर करीब 43 प्रीमियम ट्रेनें विभिन्न व्यस्त मार्गों पर चलाई जा रही हैं. जिनकी टिकट दर प्रत्येक टिकट की बुकिंग के बाद बढ़ जाती है और इनकी बुकिंग **शेष पेज 6 पर...**

रेलवे देश के विकास और परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है –सुरेश प्रभु, रेलमंत्री

हरियाणा को निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत रेल कोच फैक्टरी का तोहफा

रोहतक : रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रोहतक रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आने वाले समय में रेलवे के कायाकल्प के लिए साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. इससे देश का विकास होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. रेलमंत्री यहां 294 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 252 किमी. लंबी रोहतक-भटिंडा-लहरा मोहब्बत रेल लाइन के विद्युतीकरण के शुभारम्भ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने केवल घोषणाओं और घोटालों पर ही **शेष पेज 7 पर...**

'पीपीपी' की तर्ज पर रेलवे में माल लोडिंग घोटाले का संदेह

नई दिल्ली. भारतीय रेल की मालढुलाई में कम से कम 4,000 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका देखते हुए सीबीआई द्वारा इस संबंध में जल्दी ही शायद कोई मामला दर्ज किया जाएगा. सीबीआई को आशंका है कि रेलवे वैगन्स के वास्तविक भार के बजाय लोडेड माल की नाप-तौल में इसे कम करके दिखाने के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की गई है. उल्लेखनीय है की सीबीआई के यह छापे दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और गुजरात आदि राज्यों यानि लगभग सभी जोनल रेलों में डाले गए हैं.

सीबीआई सूत्रों का कहना है कि वित्त वर्ष 2012-13 में रेलवे ने 1,008 मिलियन टन मालढुलाई की है. इससे 85,262 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई, जो कि इस दौरान रेलवे की कुल आय का 67 फीसद रही है. रेलवे वैगन्स में ओवर लोडिंग रोकने के लिए लोडिंग वाले स्टेशन या रास्ते में या फिर गंतव्य स्टेशन पर वैगन्स

4 हजार करोड़ रु. के घोटाले की आशंका

रेल अधिकारियों, निजी वेंडरों और फ्रेट ऑपरेटरों (पीपीपी) की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिए जाने की आशंका

का भार तौला जाता है. सीबीआई का कहना है कि कई स्थानों पर नाप-तौल के सिस्टम में इस तरह की गड़बड़ी की बात सामने आई है कि ओवर लोडिंग के बावजूद वैगन का भार स्वीकार्य सीमा में दिखाई देता है. सीबीआई के अनुसार इस मामले में रेलवे और निजी पार्टियों के नाप-तौल सिस्टम के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करके बेहद सोचे-समझे तरीके से घोटाले को अंजाम दिए जाने का संदेह है. सीबीआई ने इस कथित गड़बड़ी को कुछ रेल अधिकारियों, निजी वेंडरों और फ्रेट ऑपरेटरों की मिलीभगत से अंजाम दिए जाने की आशंका जताई है.

सीबीआई का कहना है कि वर्ष 2012-13 में हुई वास्तविक ढुलाई यदि पांच प्रतिशत भी कम करके दिखाई गई है, तो राजस्व का नुकसान 4,263 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है. यह न सिर्फ एक बड़ा वित्तीय नुकसान है, बल्कि इससे निजी फ्रेट ऑपरेटरों को भारी लाभ होता है, और रेलवे ट्रैक खराब होने के साथ रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा भी बुरी तरह से प्रभावित होती है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे ने अनुसंधान, विकास एवं मानक संगठन (आरडीएसओ), लखनऊ के परामर्श से देश भर के विभिन्न स्थानों पर रेल वैगन्स का भार तौलने के लिए 200 इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज (नाप-तौल कांटे) स्थापित किए हैं. इन इलेक्ट्रॉनिक मोशन ब्रिजों पर 15 किमी. प्रतिघंटा की गति से चल रही मालगाड़ी के वैगनों का भार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मापा जाता है.

विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्राम्बे से हो रही विदेशी कोयले की लोडिंग में भी भारी गड़बड़ी होने की आशंका जताई जा रही **शेष पेज 6 पर...**

उत्तर रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल की दुर्दशा

पैथोलॉजी लैब दो महीने से बंद

दिल्ली : जहां मंत्री से लेकर रेलवे के बड़े से बड़े अधिकारियों और रेलवे बोर्ड मेंबर्स आदि का इलाज किया जाता हो, उस अस्पताल की दुर्दशा हो रही, और किसी का ध्यान इस तरफ न जा रहा हो, इसे एक बड़ी प्रशासनिक विडम्बना के सिवा के कहा जा सकता है. अस्पताल की पैथोलॉजी लैब पिछले करीब दो-ढाई महीने से बंद पड़ी है. मरीजों के खून और पेशाब की जांच भी बाहरी लैब में कराई जा रही है. लगभग हर मंजिल पर किसी न किसी वार्ड की मरम्मत का काम महीनों से चल रहा है. मरीजों के लिए पर्याप्त दवाईयों का आभाव है. उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. रेल कर्मचारियों और कई अधिकारियों का भी यही कहना है कि इस आलीशान सेंट्रल हॉस्पिटल की हालत तो किसी जिला अस्पताल से भी गई-गुजरी हो गई है. उपरोक्त दयनीय स्थिति उत्तर रेलवे के पंचकुईयां रोड, कनाट प्लेस स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा साल बीत गया, मगर यहां अभी तक कुल खरीदी या जरूरत की पर्याप्त दवाईयों की भी खरीद नहीं हो पाई है. जहां हर मंजिल पर तोड़फोड़ चल रही है, वहीं अब डायलिसिस वार्ड को रिपेयरिंग के नाम पर इंजीनियरिंग विभाग को सौंप दिया गया है. बताते हैं कि इंजीनियरिंग विभाग के चार-पांच दिन में काम खत्म कर देने के प्रॉमिस पर छह-सात दिन मानकर जो भी काम सौंपा जाता है, वह अगले दो-तीन महीनों में भी पूरा नहीं होता है. इस तरह अब डायलिसिस यूनिट भी दो-तीन महीने के लिए बंद हो जाएगी और इसके मरीजों को भी निजी अस्पतालों के लिए लैब की ही तरह रेफर कर दिया जाएगा.

अधिकारियों का कहना है कि उत्तर रेलवे प्रशासन लगभग पंगु हो रहा है और किसी को भी ऐसी लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार मानकर दंडित नहीं किया जा रहा है. इसके परिणामस्वरूप कोई भी काम समय पर नहीं हो रहा है. कर्मचारी तो यहां तक कह रहे हैं कि उत्तर रेलवे प्रशासन पर तो आजकल 'अच्छा, मगर किसी काम का नहीं' (गुड फॉर नथिंग) जैसी कहावत लागू हो रही है. उनका कहना है कि नीचे से ऊपर तक सभी को इस अस्पताल की हालत के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम है, मगर बड़े अधिकारियों को लोकल परचेज से महंगी दवाईयां घर-पहुंच उपलब्ध करवाकर और उनका इलाज बड़े निजी अस्पतालों में करवा दिया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों को लावारिश छोड़ दिया गया है.

रेलवे ने गाड़ियों में घटाया मिलिट्री कोटा

दिल्ली : मिलिट्री को अब रेलवे में वेटिंग टिकट कन्फर्म कराना मुश्किल होगा. रेल मंत्रालय ने इस पर कैंची चलाने के साथ ही सभी जोनों को आदेश दिया है कि मिलिट्री आवेदनों पर खुद फैसला लें. रक्षा मंत्रालय भी इस संबंध में रेल मंत्रालय से नहीं, बल्कि सम्बंधित जोनों से पत्राचार करेगा. मिलिट्री कोटा कम करने और कुछ ट्रेनों में इसे रद्द करने के आदेश दे दिए गए हैं. मिलिट्री का अधिकांश ट्रेनों में कोटा होता है. अब रेल मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि जिन ट्रेनों में मिलिट्री कोटा सिर्फ दस फीसदी इस्तेमाल होता है, उनमें पूरा कोटा रद्द करके उसे सामान्य यात्रियों के कोटे में समाहित कर दिया जाए. यदि दस से तीस फीसदी कोटा इस्तेमाल होता है, तो उस ट्रेन में कोटा पचास फीसदी कम किया जाए. इसके अलावा यदि तीस फीसदी से अधिक कोटा मिलिट्री लेती है, तो उस ट्रेन में कोटा बरकरार रहेगा. रेल मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को बर्थ/सीट आवंटित करने के मामले में मंत्रालय की जगह अब सम्बंधित जोनल रेलवे से पत्राचार करने की हिदायत जारी की है. इसके बाद मंत्रालय संबंधित जोन से पत्राचार कर बर्थ/सीट के बारे में जानकारी लेकर रक्षा मंत्रालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगा कि सीट मिलेगी या नहीं. इस प्रक्रिया में समय खराब होने के साथ ही रेल अधिकारियों पर वर्कलोड भी बेवजह बढ़ जाता है. यदि अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद या लखनऊ मंडल में वेटिंग टिकट कन्फर्म करवानी है, तो रक्षा मंत्रालय उत्तर रेलवे के मुख्यालय से पत्राचार करेगा. अन्य स्टेशनों के लिए संबंधित जोन से पत्राचार करना होगा. मुख्यालय देखेगा कि जिन ट्रेनों में 90 प्रतिशत से अधिक कोटा रेलवे खुद इस्तेमाल कर रहा हो, उसमें मिलिट्री को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी.

एलियंस की डायरी में लालू यादव

व्यंग्य : अतुल मिश्रा

एलियंस की एक डायरी किसी वैज्ञानिक को मिली, जिसे पढ़कर वह हैरान रह गया कि प्रथ्वी के बारे में वे लोग वही सोचते हैं, जो हम लोग खुद अपने बारे में मन करते हुए भी कभी सोचना नहीं चाहते. किसी अखबार के हवाले से आज जो भी पता चला है, वह उस डायरी के बारे में ज़्यादा है, जो हिंदी में अपने पटना-प्रवास के दौरान एलियंस द्वारा लिखी गयी थी और जब वह वैज्ञानिक अपनी पालतू भैंस को चारा डालने गया था, तो उसकी सहचरी भैंस ने सिर्फ़ इसलिए वह डायरी चबा ली कि उसे पहले चारा क्यों नहीं डाला गया? बहरहाल, डायरी तो भैंस के इस दुनिया में न होने की अहम् वजह से आज इस दुनिया में नहीं है, मगर वह वैज्ञानिक से ज़्यादा अखबार वालों के सामने कुछ सवाल खड़े कर रही है. भैंस द्वारा चबा ली गयी उस डायरी के कुछ अंश आज भी उस वैज्ञानिक को याद हैं. उसकी शुरूआत में ही लिखा है कि हम प्रमाणित करते हैं कि 'हम सब जो धोखे से अपनी यह डायरी यहां छोड़े जा रहे हैं, यह हमारी ही है और इसमें हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम प्रथ्वी वासियों को जलील करें या उन्हें उनकी औक़ात दिखा दें कि फ़िलहाल उनकी दुनिया क्या है और अगर वे चाहते तो क्या हो सकती थी? हम लोग शान्ति के साथ अपने ग्रह पर ही रहने में खुश हैं. पहले हमने सोचा था कि प्रथ्वी पर चलकर कोई सरकारी ज़मीन ले लेंगे, मगर यहां आकर पता चला कि वह ज़मीन, जो हमने पसंद की थी, वह नेताओं ने कब्ज़ा रखी है और इस जन्म में हमें नहीं मिल सकती, लिहाज़ा हमने फ़ैसला कर लिया कि हम अपने ग्रह पर ही घिचपिच में रह लेंगे, मगर इस ग्रह पर मीडिया कि सुर्खियां बनने के लिए कभी भी नहीं आयेंगे.'

एलियंस की इस चबा ली गयी डायरी में साफ़-साफ़ लिखा है कि 'हम जाना तो कहीं और चाहते थे, मगर किसी इंडिया नामक मुल्क के पटना नामक शहर में हमारे यान का ईंधन ख़त्म हो गया और हमें वहीं उतरना पड़ा. यहां ईंधन तो हमें 'ब्लैक' नामक किसी ख़ास व्यवस्था की वजह से नहीं मिला, मगर यह जानकारी ज़रूर मिली कि यहां पर हमसे मिलते-जुलते कुछ ऐसे प्राणी ज़रूर रहते हैं, जो नेतागीरी के अलावा और कोई काम नहीं करते. ज़्यादा जानकारी करने पर हमें बताया गया कि यहां पर खुद से गयी-गुज़री समझी जाने वाली भैंसों का चारा खाने वाले लोग भी रहते हैं और अगर ज़्यादा दिन तक हम यहां पर रुके, तो हमारा बचा-खुचा चारा, जिसे हम लोग 'खाना' कहते हैं, भी खा लिया जाएगा और फिर डकार भी नहीं ली जाएगी कि कोई सबूत भी रहे.

डायरी में आगे लिखा था कि यहां के चिड़ियाघर को देखने की इच्छा ज़ाहिर करने पर हमें किसी लालू प्रसाद यादव नामक प्राणी के घर पर छोड़ दिया गया कि यहां पर सभी किस्म के प्राणी आते-जाते मिल जाएंगे. हमने उक्त प्राणी के घर के दरवाज़े पर जब दस्तक दी, तो दातून नामक कोई चीज चबाते हुए कोई प्राणी बाहर आया और हमसे अजीब किस्म की भाषालापी शैली में पूछने लगा कि 'क्या हमारी ससुराल से आये हो?' हमारे ख़ामोश रहने पर फिर हमसे पूछा गया कि 'भाई, बोलते काहे नहीं हो कि हमारी पार्टीवा ज्वाइन करने आये हो?' इस दौरान हमने देखा कि सवाल पूछने वाले के कानों के पास इतने बाल उग आये थे, जितने उसके पूरे सिर पर भी नहीं रहे होंगे. हमने वहां की ज़मीन के नमूने लिए और किसी तरह ईंधन का जुगाड़ करके अपने ग्रह की तरफ निकल लिए, ताकि इस पर हम रिसर्च करके यह अंदाजा लगा सकें कि चारा खाकर भी कोई आदमी कैसे ज़िन्दा रह सकता है? डायरी के अंत में नीतीश कुमार नाम के किसी एलियंस के हस्ताक्षर साफ़ दिखाई दे रहे थे.

लोको पायलट और गार्ड को ट्रैक पर मरने वालों की लाशें ढोने का तुगलकी फरमान

दिल्ली : स्थानीय रेल प्रशासन आए दिन कई प्रकार के बचकाने और विवादास्पद निर्णय लेकर खुद को और कर्मचारियों को भी सांसत में डालता रहता है. गत वर्ष मध्य रेलवे प्रशासन ने रेल लाइन क्रॉस करते समय घायल होने वाले यात्रियों के लिए मोटरमेन कैब में स्ट्रेचर रखवा दिया था और घायलों को उठाकर स्टेशन मास्टर को सौंपने की जिम्मेदारी मोटरमैनों के गले मढ़ दी थी. अब उत्तर रेलवे ने भी ऐसा ही निर्णय लिया है.

उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल ने लाइन क्रासिंग में ट्रेन से कटकर मरने वाले या ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं में ड्राइवर को गाड़ी रोक कर इन लाशों को विभाग की तरफ से मिले कफन में बांधकर नजदीक की आरपीएफ पोस्ट या स्टेशन तक ले जाने का फरमान जारी किया है. इस फरमान से पूरे दिल्ली मंडल के लोको पायलट और गार्डों के बीच हड़कम्प मचा हुआ है. 19 मार्च को जारी इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारियों को इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए.

लोको पायलट क्षुब्ध

यहां यह सवाल उठता है कि ऐसे अमानवीय फरमान से ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट अगर क्षत-विक्षत लाशों को ढ़ोकर अगले स्टेशन तक ले आएंगे, तो क्या उनकी मन:स्थिति ऐसी रह जाएगी कि वे ट्रेन में सवार यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचा पाएं? सभी लोको पायलट्स एवं गार्डों ने इसका विरोध किया है. उनका कहना है कि ऐसे प्रत्येक हादसे में वह पूरी जिंदगी के लिए पुलिस केस में एक पार्टी बन जाएंगे. यदि ट्रेन का पायलट ट्रेन रोक कर लाश उठाता है, तो वह स्थानीय ग्रामीणों के गुस्से का भी शिकार हो सकता है. यदि वह लाश को उठाकर ले जाता है तो ट्रैक और घटनास्थल से सारे सबूत भी नष्ट हो जाएंगे.

उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल के इस तुगलकी फरमान से लोको पायलट काफी क्षुब्ध हैं. लोको पायलट पहले ही अपनी ड्यूटी के घंटों को लेकर परेशान हैं. उस पर इस तरह के आदेश निश्चित तौर पर लोको पायलट को आहत करने वाले हैं. लोको पालयट से जुड़े संगठन भी इस मामले को रेलवे बोर्ड तक ले जाने की बात कर रहे हैं. उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल का बेतुका फरमान लोको पायलट को पसंद आना तो दूर, उनके गले से नहीं उतर रहा और विवाद बढ़ने की पूरी आशंका है.

चतुर्थ श्रेणी के 44 पदों का एमटीएस के रूप में एकीकरण

दिल्ली : छठवें वेतन आयोग में हुए एक बड़े फैसले को रेलवे में अब लागू किया जा रहा है. इसमें ग्रुप 'डी' के ग्रेड पे-1500 में आने वाले 44 पदों को खत्म कर एक पद में परिवर्तित किया जा रहा है. अब इन कर्मचारियों को एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के रूप में जाना जाएगा. इसके लिए कर्मचारियों की कई श्रेणियों को एक साथ मर्ज किया जा रहा है. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. एक मई से यह नई व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी.

रेलवे के दैनिक कामकाज का बड़ा हिस्सा पोर्टर, मार्कर, रिकार्ड शार्टर, क्लीनर, अटेंडेंट, चौकीदार, पानीवाला, सफाईवाला, चपरासी, जमादार, संदेश वाहक, प्वाइंट्समैन, गेटमैन, ट्रॉलीमैन, हेल्पर, खलासी, माली, धोबी और कोट अटेंडेंट ही निपटाते हैं, लेकिन अब यह सभी पुराने पदनाम इतिहास का हिस्सा हो जाएंगे. छठवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी के पदनाम खत्म कर दिए थे. इनकी जगह ग्रेड पे-1800 में आने वाले पदों को एमटीएस का नया पदनाम दिया था. डीओपीटी के वर्ष 2010 में जारी हुए आदेश के बाद ज्यादातर केंद्रीय विभागों में यह व्यवस्था लागू भी हो गई है, लेकिन रेलवे में इस पर अब तक अमल नहीं किया गया था. अब जैसे ही सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं, तब रेलवे ने पुरानी योजना को लागू करने की फाइल आगे बढ़ाई है. रेलवे बोर्ड के सचिव ने ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) के महासचिवों को बोर्ड के इस प्रस्ताव की जानकारी दी है. इसमें ग्रुप 'डी' से 2550 से 3200 और 2750 से 4400 वेतनमान वाले सभी पदों का मर्जर किया जाना है. वर्तमान पदों में वरिष्ठ और सहायक जैसी श्रेणियां भी हैं. लेकिन एमटीएस में पदनाम के आगे कोई भी सीनियर, जूनियर या असिस्टेंट जैसे शब्द नहीं लगेंगे. एमटीएस नाम को रेलवे के पदों के मानकीकरण समिति ने तय किए हैं.

सीबीआई ने सीनियर डीईई/पॉवर/मुंबई सेंट्रल को एक लाख लेते रंगेहाथ पकड़ा

मुंबई. पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल मंडल के वरिष्ठ मंडल विद्युत् अभियंता/पॉवर (सीनियर डीईई/पॉवर) मीना को सीबीआई ने एक कांट्रेक्टर से एक लाख रुपए नकद रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा है. यह घटना मंगलवार, 21 अप्रैल की देर शाम करीब 8.30 बजे से 9 बजे के बीच की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मीना यह रकम उक्त कांट्रेक्टर को मंडल कार्यालय में लगे एयर कंडीशनर के रख-रखाव का वार्षिक ठेके दिए जाने की एवज में ले रहे थे. बताते हैं कि सम्बंधित कांट्रेक्टर ने ही मीना की इस रिश्वतखोरी की शिकायत सीबीआई से की थी. जिसके बाद सीबीआई ने प्रॉपर ट्रैप लगाकर उन्हें रंगेहाथ गिरफ्तार किया है.

उल्लेखनीय है कि बहुत ही मीठा-मीठा बोलने वाले सीनियर डीईई/पॉवर मीना इस 'धंधे' में रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच बहुत बदनाम रहे हैं. इसी वजह से कई कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुंबई सेंट्रल मंडल में ठेके पर काम लेना ही बंद कर दिया था. हाल ही में रविवार, 29 मार्च को उनके ही इशारे पर एसएसई/पॉवर, बोरीवली ने रवीन्द्र कुमार सिंह नामक इलेक्ट्रिकल कांट्रेक्टर को अपने कार्यालय में बुलाकर उसकी जमकर पिटाई की थी, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी. 'रेलवे समाचार' ने यह खबर 'रेलवे कांट्रेक्टर के साथ मारपीट, दोनों पक्षों द्वारा पुलिस में क्रॉस एफआईआर दर्ज' शीर्षक से प्रकाशित की थी. सफल ट्रैप के बाद सीबीआई ने सीनियर डीईई मीना के कार्यालय और आवास की भी तलाशी ली है, जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं. कई कॉन्ट्रैक्टर्स और रेलकर्मियों का कहना है कि मीना की ज्यादती और लगातार इस प्रकार की भ्रष्ट गतिविधियों के चलते एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था.

सुरेश प्रभु ने किया जे.जी.माहुरकर लिखित 'द गार्डियन' का विमोचन

मुंबई. वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ (डब्ल्यूआरएमएस) के महामंत्री और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) के उपाध्यक्ष जे. जी. माहुरकर द्वारा लिखित आत्मकथा 'द गार्डियन' का विमोचन रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने 18 अप्रैल 2015 को मुंबई सेंट्रल स्थित रेलवे इंस्टिट्यूट 'रेल निकुंज' में किया. इस अवसर पर एनएफआईआर के महामंत्री डॉ. एम. राघवैया सहित मध्य एवं पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक एस. के. सूद, पूर्व महाप्रबंधक के. सी. जेना, सीआरएमएस के अध्यक्ष आर. पी. भटनागर, महामंत्री प्रवीण बाजपेयी, डब्ल्यूआरएमएस के अध्यक्ष शरीफ खान, मंडल मंत्री अजय सिंह तथा बड़ी संख्या में पश्चिम और मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, डब्ल्यूआरएमएस के सभी मंडलों के मंडल मंत्री एवं रेल कर्मचारी उपस्थित थे.

डब्ल्यूआरएमएस के महामंत्री जे. जी. माहुरकर द्वारा लिखित आत्मकथा 'द गार्डियन' का विमोचन करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु. उनके साथ हैं बाएं जे. जी. माहुरकर, डब्ल्यूआरएमएस के अध्यक्ष शरीफ खान, मंडल मंत्री अजय सिंह. और दाएं हैं एनएफआईआर के महामंत्री डॉ. एम. राघवैया, पूर्व महाप्रबंधक के. सी. जेना और मध्य एवं पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक एस. के. सूद.

महाराष्ट्र सरकार द्वारा 'द्रोणाचार्य' पुरस्कार से पुरस्कृत श्री जसवंतराव गुलाबराव माहुरकर (दादा) ने अपने इस आत्मकथा (जीवनी) में अपने लम्बे ट्रेड यूनियन अनुभव को साझा किया है. उनकी इस जीवनी का विमोचन करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्येक रेलकर्मी को अपना आत्मकथा लिखना चाहिए. श्री माहुरकर ने कहा कि आत्मकथा लिखना काफी मुश्किल काम है. उन्होंने रेलमंत्री सहित आत्मकथा लिखने में मदद करने और इसके लिए प्रोत्साहित करने वाले सभी लोगों को इस मौके पर धन्यवाद दिया. श्री राघवैया ने इस अवसर पर सभी रेलकर्मियों को काम और कर्तव्य के प्रति समर्पण और निष्ठा के लिए श्री माहुरकर से प्रेरणा लेने की बात कही.

महाप्रबंधक/म.रे. के आदेश पर ठाणे स्टेशन स्थित महानंदा स्टाल को लगा ताला

ठाणे. मध्य रेल के महाप्रबंधक सुनील कुमार सूद के आदेश से ठाणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7-8 पर स्थित 'महानंदा डेरी पार्लर' के स्टाल को मुंबई मंडल प्रशासन ने सोमवार, 20 अप्रैल को ताला लगा दिया. उल्लेखनीय है कि इस स्टाल के खिलाफ विगत में कई लिखित शिकायतें हो चुकी थीं. इसके खिलाफ आरटीआई में भी जानकारी मांगी गई थी, कि इस स्टाल पर किन-किन वस्तुओं की अधिकृत बिक्री की जा सकती है. मगर मंडल के एक वाणिज्य अधिकारी और ठाणे स्टेशन पर तैनात वाणिज्य निरीक्षक की मिलीभगत के कारण लम्बे समय से स्टाल धारक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार महानंदा डेरी पार्लर स्टाल पर सिर्फ महानंदा डेरी के ही उत्पादों की बिक्री किए जाने की अधिकृत अनुमति रेल प्रशासन ने दी है. मगर आरोप है कि इस स्टाल पर पीने का पानी, नमकीन, बिस्किट आदि तमाम खानपान वस्तुएं बेचीं जा रही थीं. इसके अलावा यह भी आरोप है कि इस स्टाल धारक द्वारा अनधिकृत तौर पर स्टेशन और मेल-एक्स. गाड़ियों में अवैध हाकर भी चलाए जा रहे थे. वैसे तो मंबई मंडल, मध्य रेलवे में सीएसटी से लेकर कुर्ला टर्मिनस, दादर टर्मिनस, घाटकोपर, ठाणे, कल्याण, कसारा और इगतपुरी तक लगभग सभी बड़े स्टेशनों पर अवैध हाकरों की भरमार है. जो कि स्टेशन सहित मेल/एक्स. गाड़ियों में खानपान की अवैध बिक्री करते हैं. इन अवैध हाकरों और इनको चलाने वाले स्टाल धारकों को उक्त स्टेशनों पर तैनात वाणिज्य निरीक्षकों और मंडल के कुछ वाणिज्य अधिकारियों सहित आरपीएफ/जीआरपी का भी भरपूर सहयोग तथा वरदहस्त प्राप्त है. बताया जाता है कि महाप्रबंधक/म.रे. पर व्यक्तिगत आरटीआई का दबाव होने के चलते अब महानंदा डेरी पार्लर स्टाल को शील किया जा सका है.

बताते हैं कि लम्बे समय से महानंदा डेरी पार्लर के खिलाफ अनधिकृत वस्तुओं की बिक्री किए जाने की लिखित शिकायतें हो रही थीं, मगर मंडल प्रशासन के कान में जूं भी नहीं रेंग रही थी, क्योंकि इस स्टाल को चलाने वाले के साथ कुछ सम्बंधित वाणिज्य अधिकारियों की मिलीभगत चल रही रही थी. जानकर बताते हैं कि इस व्यक्ति ने मंडल के कई असली स्टाल धारकों को मोटी राशि देकर उनके स्टाल अपने कब्जे में ले लिए हैं. जानकारों का कहना है कि इन स्टालों पर अवैध रूप से अनधिकृत वस्तुओं की बिक्री की जा रही है, जिसे इसके साथ मिलीभगत होने के चलते कभी चेक नहीं किया जाता है.

तिकड़मबाजी के चक्कर में नप गए पू.उ.रे. के डिप्टी सीपीओ/गज.

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे में करीब 20-22 साल से गोरखपुर में ही जमे डिप्टी सीपीओ/गजटेड का आखिर तबादला कर दिया गया है. तथापि उन्हें डिप्टी सीपीओ/वर्कशॉप, गोरखपुर के पद पर भेजा गया है. उनके इस तबादले से पूर्वोत्तर रेलवे के लगभग सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. जबकि डिप्टी सीपीओ/वर्कशॉप रहे अधिकारी को डिप्टी सीपीओ/नॉन-गजटेड के पद पर और डिप्टी सीपीओ/नॉन-गजटेड को डिप्टी सीपीओ/गजटेड के पद पर पदस्थ किया गया है. इससे जाहिर है कि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री राजीव मिश्रा ने एक बातचीत के बाद कुछ कारगर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

उल्लेखनीय है कि डिप्टी सीपीओ/गजटेड रहे अधिकारी को ग्रुप 'बी' एलडीसीई में अपने ही मातहत कार्यरत रही अपनी ओएस बीवी को फेवर करने और जानबूझकर एलडीसीई परीक्षा रद्द कराने की तिकड़म करने से सम्बंधित शिकायतों के चलते ट्रांसफर किया गया है. उन्होंने सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों का रिजल्ट घोषित किया था, मगर आरक्षित वर्ग के किसी भी परीक्षार्थी का परिणाम घोषित नहीं किया था. यहां तक कि नियमानुसार 'बेस्ट अमंग फेल्योर' में भी इस वर्ग के परीक्षार्थियों का परिणाम नहीं निकाला था. इस संबंध में हुई शिकायतों के बाद यह परिणाम घोषित किए गए. फिर भी वह किसी भी तरह इस परीक्षा को रद्द कराने की जुगाड़ में लगे रहे. इसके लिए उन्होंने खुद से लिखकर अपनी बीवी की तरफ से शिकायत की थी. जबकि उनकी बीवी अंग्रेजी में एक भी सही वाक्य लिखने की क्षमता नहीं रखती है. इसके अलावा खुद की लिखी शिकायत को बड़ी ठसक के साथ खुद ही डील भी कर रहे थे. ट्रांसफर्ड डिप्टी सीपीओ/गजटेड की तिकड़म यहीं समाप्त नहीं होती है. उन पर यह भी आरोप है कि बीवी को फेवर करने और किसी तरह उसे अधिकारी बनाने के चक्कर में करीब दो साल पहले हुई वाणिज्य विभाग की 30त एलडीसीई की लिखित परीक्षा के जो परिणाम लगभग चार महीने पहले घोषित हुए थे, उसका अंतिम रिजल्ट नहीं निकाल रहे थे. इसके चलते कई कर्मचारी परेशान हो रहे थे और उनका काफी नुकसान भी हो चुका है. कर्मचारियों द्वारा की गई विभिन्न शिकायतों का पुलिंदा 'रेलवे समाचार' के पास मौजूद है. बताते हैं कि इन तमाम तिकड़मों और लापरवाहियों के लिए अब उन्हें जल्दी ही मेजर पेनाल्टी चार्जशीट भी दी जा सकती है.

डिप्टी सीएमएम का निलंबन रद्द,

महाप्रबंधक ने दिया समझदारी का परिचय

उधर वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि पिछले करीब एक साल से 70त एलडीसीई की कापियां न जांचने वाले सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ भी महाप्रबंधक को उचित विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए. उनका कहना है कि वाणिज्य विभाग में सहायक अधिकारियों की भारी कमी हो गई है, परंतु सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साल से लिखित परीक्षा की कापियां नहीं जांची हैं. कर्मचारियों का कहना है कि जिस प्रकार निर्धारित समय पर उनके तबादले किए जाते हैं, उसी प्रकार सभी अधिकारियों के भी तबादले किए जाने चाहिए. उनका यह भी कहना है कि जो अधिकारी 20-25 सालों से पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में ही पदस्थ हैं, उन्हें अविलंब अन्य जोनल रेलों में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि लम्बे समय से एक ही शहर और एक ही विभाग में पदस्थ होने से स्थानीय स्तर पर इनके बहुत गहरे असामाजिक संबंध बन गए हैं, जिसका नाजायज इस्तेमाल कर्मचारियों को डराने-धमकाने और भ्रष्टाचार करने के लिए किया जाता है.

महाप्रबंधक ने डिप्टी सीएमएम के विवादित निलंबन को भी वापस लेकर अत्यंत समझदारी का काम किया है. इससे न सिर्फ स्टोर कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों में फैला आक्रोश खत्म हुआ है, बल्कि उन्होंने इस मामले में महाप्रबंधक की तारीफ भी की है. उनका कहना था कि महाप्रबंधक जब किसी समस्या को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो वह उसके निवारण के लिए सही कदम उठाने से पीछे नहीं हटते हैं. अब कर्मचारियों की मांग यह है कि इस पूरे मामले में दोषी और जिम्मेदार रहे सीडब्ल्यूएम को वर्कशॉप से फौरन हटाया जाना चाहिए, जो कि न सिर्फ वहां पिछले 4-5 साल से बैठे हैं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जुगाड़ में लगे होने के कारण उनका कोचों के आउट पुट पर कोई ध्यान नहीं रहा है. जबकि उनकी और अन्य अधिकारियों की गलती का खामियाजा मात्र डेढ़-दो महीने पहले पदस्थ हुए एक डिप्टी सीएमएम को भुगतना पड़ा है, जिसके लिए वह कतई जिम्मेदार नहीं था. हालांकि अब सम्बंधित डिप्टी सीएमएम का भी तबादला किए जाने की आशंका हो रही है, जिसका उनके निलंबन से कोई संबंध नहीं है. तथापि, यह उन्हें ग्रुप 'ए' मिलने के कारण ड्यू हो गया है. मगर फिलहाल यदि उनका यह तबादला होता है, तो कर्मचारियों में उसका गलत संदेश जा सकता है.

इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री राजीव मिश्रा ने 'रेलवे समाचार' से टेलीफोनिक बातचीत में कहा कि उन्होंने चार साल से ज्यादा एक पद पर और एक ही जगह पदस्थ कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया है. अब अधिकारियों की बारी है. उन्होंने यह भी कहा कि यह काम जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में आने के इच्छुक योग्य अधिकारियों के मिलते ही यह काम भी तेजी किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद इस संबंध में रेलवे बोर्ड से बात कर चुके हैं. 15-20 मिनट की इस लंबी बातचीत में 'रेलवे समाचार' ने महाप्रबंधक से यह भी कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे की बदनामी और इसकी तीव्र प्रगति में यहां लम्बे समय से पदस्थ कुछ अधिकारी और कर्मचारी बहुत बड़ी बाधा हैं. इस समस्या पर रेल प्रशासन को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए. इस पर महाप्रबंधक ने पूर्वोत्तर रेलवे की सफाई पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की बात कही है.

महाप्रबंधकों की नियुक्तियों पर अड़ कर बैठा डीओपीटी

सुरेश त्रिपाठी

भारतीय रेल की गाड़ियां कभी निर्धारित समय पर नहीं चलती हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक तौर पर पूछ लिए जाने पर रेलमंत्री ने कुछ दिनों तक इस विषय में कुछ सख्ती दिखाई, मगर अब यह पुनः पुराने ढ़र्रे पर ही चल पड़ी हैं. यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि भारतीय रेल का कोई भी काम कभी-भी अपने निर्धारित समय पर नहीं होता है. पिछले चार महीनों से पांच जोनल महाप्रबंधकों के पद खाली पड़े हुए हैं, जिनमें से एक पद तो करीब तीन साल से खाली है, जिसका आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है. जबकि करीब दो महीने पहले पांच महाप्रबंधकों की पोस्टिंग के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है. अब 30 अप्रैल को प्रमोद कुमार के सेवानिवृत्त हो जाने से आरसीएफ, कपुरथला के महाप्रबंधक का एक पद और खाली हो गया है. उल्लेखनीय है कि प्रदीप कुमार के मेंबर स्टाफ बनने से उत्तर मध्य रेलवे, नवीन टंडन के मेंबर इलेक्ट्रिकल बनने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, राकेश मिश्रा के वीआरएस लेने से दक्षिण रेलवे और हेमंत कुमार के मेंबर मैकेनिकल बन जाने से पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के पद पिछले चार महीनों से खाली पड़े हैं. जबकि मेट्रो रेलवे कोलकाता के महाप्रबंधक का पद पी. बी. मूर्ति के बाद से पिछले करीब तीन साल से खाली है. अब प्रमोद कुमार के 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाने से आरसीएफ का भी एक पद खाली हो गया है. आरसीएफ को छोड़कर बाकी सभी पदों पर महाप्रबंधकों की नियुक्ति का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड द्वारा गत मार्च महीने के पहले हफ्ते में डीओपीटी को भेजा गया था, परंतु पहले की ही भांति डीओपीटी इस बार भी इस प्रस्ताव को दबाकर बैठ गया है और रेलवे बोर्ड को जीएम एवं डीआरएम के पदों पर नियुक्ति सम्बंधी पालिसी को स्पष्ट करने की नसीहत दे रहा है.

भारतीय रेल की प्रशासनिक हालत को सुधार पाना सुरेश प्रभु के लिए आसान नहीं है

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2014 तक जब जोनल महाप्रबंधकों के लगभग 9-10 पद खाली पड़े हुए थे और पूरी भारतीय रेल करीब-करीब बिना महाप्रबंधकों के ही चल रही थी तथा जब उपरोक्त पांच जोनल महाप्रबंधकों की रेलवे बोर्ड में नियुक्ति होने की स्थिति में सभी जोनल मुख्यालय लावारिश होने की हालत में पहुंच गए थे, तब तक जीएम पैनल भी फाइनल नहीं हुआ था. ऐसी स्थिति का ही फायदा उठाकर भारतीय रेल के अब तक के सबसे बड़े तिकड़मबाज साबित हुए पूर्व सीआरबी ने अपने सेवा-विस्तार की जुगत भिड़ाई थी. तब सरकार ने आनन-फानन में न सिर्फ डीओपीटी से जीएम पैनल फाइनल करके मंगवाया था, बल्कि रेलवे बोर्ड मेंबर्स के खाली पदों सहित एक जोन में एडवांस (ईसीआर) प्रस्ताव करते हुए पहले से खाली पड़े सभी जोनल महाप्रबंधकों की नियुक्ति प्रक्रिया को मात्र एक हफ्ते में पूरा किया था.

इस पर कई पूर्व महाप्रबंधकों और पूर्व बोर्ड मेंबर्स का कहना है कि तब डीओपीटी की पालिसी सुधारने की जिद कहां चली गई थी? एक पूर्व बोर्ड मेंबर का तो यहां तक कहना है कि डीओपीटी को पैसा खाने की बहुत बुरी लत लग गई है और उसे यह लत रेलवे बोर्ड तथा जल्दी और मनचाहा जोन पाने की चाहत रखने वाले रेल अधिकारियों ने ही विगत में लगाई है. उनका कहना है कि रेलवे के मामले में डीओपीटी द्वारा हमेशा से ऐसा ही रवैया अपनाया जाता रहा है. जब तक चारों तरफ से हो-हल्ला नहीं मचता है और दो-चार महीनों की देरी नहीं हो जाती है, तब तक डीओपीटी के कान में जूं नहीं रेंगती है. उन्होंने कहा कि किसी भी पोस्टिंग प्रस्ताव को दो-तीन महीने अटका देना डीओपीटी के लिए बहुत मामूली बात है. जब हल्ला मचता है, तो डीओपीटी द्वारा यह कहकर रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी जाती है कि 'अच्छा ठीक है, इस बार तो अनुमति दे देते हैं, मगर अगली बार अपनी पालिसी ठीक करके ही आना.' यह हाल तब है जब कार्मिक मंत्रालय (डीओपीटी) सीधे प्रधानमंत्री के मातहत काम कर रहा है.

इस पूर्व बोर्ड मेंबर ने जोनल जीएम और बोर्ड मेंबर्स की नियुक्ति के मामले में 'ऑफ द रिकॉर्ड' बातचीत के दौरान और भी बहुत गंभीर घोटाले की तरफ इशारा किया है. जोनल जीएम और बोर्ड मेंबर्स की नियुक्ति के मामले में तो आज यह भी सर्वविदित है कि पूर्व के कई मंत्री इसके लिए जीएम उम्मीदवारों से खुलेआम पैसा मांगते रहे हैं. यह बात तो तब और भी अच्छी तरह से साबित हो गई थी, जब एक बोर्ड मेंबर की नियुक्ति के मामले में रेलगेट कांड का खुलासा हुआ था. जबकि उससे पहले ऐसे सभी मामलों में यह लेनदेन होता रहा था. भारतीय रेल में जोनल जीएम और बोर्ड मेंबर्स की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादला, चार्जशीट और तबादला रद्द करना, एसीआर ठीक करना आदि ऐसे काम हैं, जिनमें हमेशा भारी लेनदेन होता रहा है. यहां तक कि रेलवे बोर्ड में प्रतिनियुक्ति सहित वहां लम्बे समय तक मलाईदार पदों पर बैठे रहने के लिए भी करोड़ों की डील होती रही है. पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कमोबेस यह काम आज भी हो रहा है. रेलमंत्री जब तक उच्च पदों पर सही समय पर नियुक्तियां सुनिश्चित नहीं करते हैं, और रेलवे बोर्ड सहित जोनल मुख्यालयों तथा एक शहर में लम्बे समय से टिके अधिकारियों को दर-बदर नहीं करते हैं, तथा सीवीसी द्वारा जारी संवेदनशील पदों पर पीरियोडिकल ट्रांसफर का नियम कड़ाई से लागू नहीं करते हैं, तब तक भारतीय रेल की आर्थिक और प्रशासनिक हालत को सुधार पाना उनके वश की बात नहीं है.

रेलवे की हालत में सुधार के लिए अब गेंद सुरेश प्रभु के पाले में है..

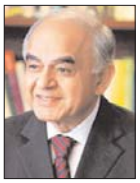

गुरचरण दास*

गर्मी की छुट्टियां और भारतीय रेल का अटूट संबंध रहा है. हर भारतीय नागरिक के मन में रेलवे को लेकर छुट्टियों में की गई यात्रा की कोई न कोई रूमानी याद जरूर होती है. आज ये रूमानी यादें धुंधला गई हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ नेताओं ने लम्बे समय से रेलवे के साथ 'निजी जागीर' जैसा व्यवहार करके इसे पूरी तरह कुचल डाला है. रेलवे भारतीय व्यवस्था का लघु रूप है - अक्षम, भ्रष्ट, राजनीतिकरण से बेजार, गैर-जरूरी स्टाफ के बोझ से चरमराती असुरक्षित सेवा. सरकारी एकाधिकार और धन-आवंटन में राजनीति के कारण निवेश और नई तकनीक के लिए पैसे की तंगी इसकी मूल समस्या है. इस कारण न तो इसका विस्तार और आधुनिकीकरण हो पाया, न रफ्तार बढ़ पाई और न यह बढ़ते देश की जरूरतें पूरी कर पाई है. फिर यात्रियों की सब्सिडी का भार मालभाड़े पर डालने से यह बहुत ज्यादा बढ़ गया और ग्राहक माल ढुलाई के लिए ट्रकों की ओर मुड़ गए.

लगभग सारे लोकतांत्रिक देशों ने रेलवे में सरकारी एकाधिकार की निजी भागीदारी को लाकर स्पर्धा को बढ़ावा दिया है. इसके बाद सभी जगह शानदार नतीजे मिले हैं. भारतीयों ने 1991 के बाद से देखा है कि एकाधिकार बुरा ही होता है. उन्होंने प्रतिस्पर्धा के कारण आई संचार क्रांति को देखा है. 20 साल पहले कौन सोच सकता था कि गरीब से गरीब भारतीय के पास भी फोन होगा ! भारत में अब 1990 के 50 लाख की तुलना में 99 करोड़ फोन हैं. प्रतियोगिता के कारण टेलीफोन सेवाओं की कीमतें नीचे आई हैं, सेवाओं में सुधार हुआ है, इनोवेशन को बढ़ावा मिला है और भ्रष्टाचार में कमी आई है. सौभाग्य से रेलवे के लिए अब असली उम्मीद जागी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आधुनिक बनाने का संकल्प लिया है और सुरेश प्रभु के रूप में उनके पास रेलवे के इतिहास के सर्वाधिक कार्यकुशल और ऊर्जावान रेलमंत्री हैं. गठित की गई विभिन्न विशेषज्ञ समितियों से पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है. इसमें नवीनतम है बिबेक देबराय समिति, जिसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट ऑनलाइन जारी कर दी है, ताकि जनता की राय ली जा सके. अन्य देशों के रेलवे संगठनों के सुधारों से मिले सबक के आधार पर निम्नलिखित ऐसे दस कदम उठाए जा सकते हैं, जो भारतीय रेल के वैभव को बहाल कर सकते हैं.

1. जैसा कि सारे पेशेवर उपक्रमों में होता है, मालिक और प्रबंधन के बीच दूरी बनानी होगी. यहां मालिक सरकार है, जिसका प्रतिनिधित्व रेल मंत्रालय करता है. वह रेल क्षेत्र के लिए सिर्फ नीतियां बनाए और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे. ट्रेनें चलाने वालों को संचालन संबंधी स्वायत्तता देनी चाहिए. भविष्य में अलग रेल बजट की जरूरत नहीं है और इसका परिवहन मंत्रालय में विलय कर दिया जाना चाहिए.
2. भारतीय रेल को दो स्वतंत्र संगठनों में बांट दिया जाना चाहिए. दोनों का स्वामित्व सरकार के पास रहे. एक पर रेलवे ट्रैक तथा आधारभूत ढांचे की जिम्मेदारी हो और दूसरा निजी क्षेत्र के साथ स्पर्धा में ट्रेनों का संचालन करे. इन दोनों सार्वजनिक संगठनों के अपने बोर्ड हों, जिसमें स्वतंत्र एवं कार्यकारी निदेशक हों. राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए इन संगठनों का निजीकरण ठीक नहीं होगा.
3. स्वतंत्र नियामक यानी रेगुलेटर की स्थापना हो, ताकि रेलवे ट्रैक का निष्पक्ष इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके. कॉमन ट्रैक पर ट्रेनें चलाने के लिए शुल्क तय कर जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. रेग्यूलेटर सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होगा.
4. मालवाही और यात्री ट्रेनों को स्पर्धा में उतारें. निजी स्पर्धा को आकर्षित करने के लिए स्वतंत्र नियामक और स्वतंत्र ट्रैक संगठन का होना जरूरी है, ताकि निजी क्षेत्र आश्वस्त रहे कि स्पर्धा निष्पक्ष होगी.
5. भारतीय रेलवे को स्कूल, अस्पताल, प्रिंटिंग प्रेस चलाना, वॉटर बॉटलिंग करना और पुलिस बल के संचालन आदि जैसी गतिविधियों को छोड़कर सिर्फ ट्रेनों के संचालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. रेलवे के 13 लाख से अधिक कर्मचारियों में से ज्यादातर इन्हीं गतिविधियों में लगे हैं, जो संसाधनों की बर्बादी है. इससे कर्मचारियों का ध्यान भटक जाता है.
6. रेलवे की उत्पादन और निर्माण इकाईयों को स्वायत्तता दीजिए, ताकि उन्हें पेशेवर कंपनियों की तरह चलाया जा सके. वे बाजार से पूंजी जुटा सकें और देश-विदेश की रेल कंपनियों से बिजनेस में स्पर्धा कर सकें.
7. दोनों रेल संगठनों में जनरल और डिवीजनल मैनेजरों को टेंडर जारी करने, खरीद और वित्तीय सहित सारे मामलों में अधिक स्वायत्तता दीजिए.
8. रेलवे के फाइनेंशियल अकाउंट्स को आधुनिक बनाना होगा, ताकि बेहतर निर्णय प्रक्रिया और निवेशकों से फंड लेने में सहूलियत रहे. आज रेलवे के लिए मौजूदा रूट की लाभप्रदता अथवा नई परियोजना पर वास्तविक प्राप्ति का आकलन करना बहुत कठिन है.
9. उपनगरीय और स्थानीय यात्री रेल सेवाओं को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में चलाने दीजिए. राज्यों को संघवाद की सच्ची भावना से सब्सिडी वहन करनी चाहिए. फिलहाल रेलवे इसलिए घाटे में है, क्योंकि राज्य सरकारें इसकी दरें बढ़ने देना नहीं चाहतीं.
10. रेलवे को स्वस्थ व्यावसायिक उपक्रम बनाना है, तो उसे इनवेस्टमेंट बैंकों की मदद से, असेट्स के उपयोग से संसाधन जुटाने होंगे. अभी रेलवे 'राजनीतिक किराये' से पीड़ित है, जिनसे इसकी संचालन लागत भी वसूल नहीं होती और यह घाटे में चली जाती है. रेलवे को सब्सिडी के लिए सरकार से भीख मांगनी पड़ती है. चूंकि सरकार के पास तो हमेशा ही तंगी रहती है, रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कभी पैसा नहीं मिल पाता है. किंतु यदि राजनेताओं को रेलवे के संचालन से अलग कर दिया जाए, तो अतिरिक्त जमीन बेचकर और स्टेशनों के एयर स्पेस पर निर्माण कर, उन्हें किराए पर देकर या बेचकर संसाधन जुटाए जा सकते हैं.

भारत की राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए समझदारी इसी में है कि रेलवे को निजी हाथों में न सौंपा जाए, बल्कि रेल क्षेत्र में स्पर्धा पैदा की जाए. इससे कर्मचारी अधिक प्रेरित और जवाबदेह होंगे, जिन्हें नेताओं के हस्तक्षेप के खिलाफ संरक्षण मिलेगा. उनका बोनस लाभप्रदता से जुड़ेगा, तो सरकार उनकी पेंशन की रक्षा करेगी. अब गेंद रेलमंत्री सुरेश प्रभु के पाले में है. यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ये दस कदम उठा सकता है, तो वे सुरेश प्रभु ही हैं. पूर्व में कई विशेषज्ञ समितियां बनी हैं, लेकिन रेलवे हमेशा उनकी सिफारिशें लागू करने से बचने में कामयाब रही. आइए, उम्मीद करें कि मोदी सरकार भारतीय जनता के हित में सही कदम उठाकर दिखाएगी.

रेलवे के पुनर्गठन के लिए बनी उच्चस्तरीय देबराय समिति के सदस्य

gurcharandas@gmail.com

सीनियर डीईएन, धनबाद मंडल बी. के. सिंह को महाप्रबंधक पुरस्कार

60वें रेल सप्ताह के अवसर पर उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं और तत्परतापूर्वक कार्य-निष्पादन के लिए पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल अभियंता (सीनियर डीईएन2) बी. के. सिंह (आईआरएसई-1997 बैच) महाप्रबंधक आदित्य कुमार मित्तल से प्रशस्ति पत्र, पदक और नकद पुरस्कार ग्रहण करते हुए. उन्हें यह पुरस्कार गोमोह यार्ड की आरआरआई कार्य पूर्व निर्धारित समयावधि से 3 दिन पहले 20 जून 2014 को पूरा कर लेने पर दिया गया है. इस आरआरआई कार्य के अंतिम चरण में लगभग 45 नए पॉइंट्स लगाए गए हैं और 7 डायमंड क्रासिंग्स को यार्ड से हटाने का

रेलमंत्री ने जारी किया अनारक्षित रेल टिकटों के लिए मोबाइल ऐप

पायलट परियोजना के तौर पर कागजरहित अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम (यूटीएस) के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारम्भ करते हुए रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभु के साथ चेयरमैन, रेलवे बोर्ड श्री ए. के. मितल और मेंबर ट्रैफिक श्री अजय शुक्ला. साथ में हैं एडीशनल मेंबर (सीएंडआईएस) मोहम्मद जमशेद.

दिल्ली : रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रेल भवन में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेल को डिजिटल इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए बुधवार, 22 अप्रैल को कागजरहित अनारक्षित टिकटों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन (ऐप) लांच किया. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली से दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चेन्नई में एगमोर और ताम्बरम उपनगनीय खंड के यात्रियों के लिए कागजरहित अनारक्षित टिकटिंग के लिए मोबाइल ऐप का शुभारम्भ किया. सेंटर फॉर रेलवे इंफरमेशन सिस्टम (क्रिस) द्वारा विकसित 'यूटीएस ऑन मोबाइल' का उद्देश्य अनारक्षित टिकटों की प्रिंटिंग की जरूरत खत्म करना है.

श्री प्रभु ने इस डिजिटल प्रणाली की शुरूआत करने के बाद कहा कि अनारक्षित क्षेत्र में कागजरहित टिकटें उपलब्ध कराने की घोषणा रेल बजट में की गई थी. उसे आज हमने इसे लागू कर दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे रेलवे टिकटिंग प्रणाली की कार्यक्षमता और पारदर्शिता को बढ़ाने में पर्याप्त मदद मिलेगी. श्री प्रभु ने रेलकर्मियों से अपील की कि वे नए विचारों और नई तकनीक को अपनाएं, ताकि यात्री सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके. उन्होंने रिकॉर्ड समय में इस मोबाइल ऐप को तैयार करने के लिए क्रिस की सराहना करते हुए उसे चार लाख रुपए का पुरस्कार भी दिए जाने की घोषणा की.

इस अवसर पर चेयरमैन, रेलवे बोर्ड श्री ए. के. मितल ने कहा कि इस पायलट योजना के तहत अनारक्षित सीटों के लिए कागजरहित रेल टिकटिंग प्रणाली में फिलहाल दक्षिण रेलवे के एग्मोर - ताम्बरम उपनगरीय खंड के 15 स्टेशनों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि जल्दी ही सभी महानगरों के उपनगरीय क्षेत्र में कागजरहित सेवा शुरू कर दी जाएगी. इस अवसर पर मेंबर ट्रैफिक श्री अजय शुक्ला और एडीशनल मेंबर (सीएंडआईएस) मोहम्मद जमशेद भी उपस्थित थे.

उल्लेखनीय है कि यह मोबाइल टिकटिंग ऐप एंड्रायड एवं विंडोज दोनों प्लेटफार्म पर काम करता है. इसे गूगल प्ले स्टेशन या विंडो स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. रेल अधिकारियों ने बताया कि टिकट बुकिंग के दौरान यह एप्लीकेशन स्क्रीन पर जरूरी अलर्ट भी देता है. टिकट के लिए भुगतान 'रेलवे वॉलेट' के माध्यम से होगा, जो इस ऐप में मौजूद है. एक बार टिकट बुक हो जाने पर उसकी सूचना स्क्रीन पर आ जाएगी. इसमें सीमित जानकारी होगी. यात्रियों को टिकट बुक कराने के एक घंटे के भीतर करनी होगी. यात्रा के हर दिन टिकट का रंग अलग होगा, ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा. मोबाइल पर आए टिकट संबंधी मैसेज को अन्यत्र फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा. यात्री रोजाना अनारक्षित टिकटों के आधार पर यात्रा करते हैं. अनुमान है कि इस ऐप के आ जाने से एक साल में रेल टिकटों की छपाई का लगभग 1200 टन कागज बचेगा. इससे रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व की बचत होगी.

देबरॉय समिति की अंतरिम रिपोर्ट के विरोध पर रेलवे के सभी मान्यताप्राप्त फेडरेशन एकमत

डॉ. बिबेक देबरॉय समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एआईआरएफ के महामंत्री कॉम. शिवगोपाल मिश्रा और एआईआरपीएफए के महामंत्री श्री यू. एस. झा. उनके साथ हैं एआईआरएफ के अध्यक्ष श्री राखाल दासगुप्ता, एनएफआईआर के महामंत्री श्री एम. राघवैया, अध्यक्ष श्री गुमान सिंह, एआईआरपीएफए के अध्यक्ष श्री एस. आर. रेड्डी, एफआरओए के अध्यक्ष श्री आर. आर. प्रसाद और आईआरपीओएफ के महामंत्री श्री रमन कुमार शर्मा.

दिल्ली : भारतीय रेल में मान्यताप्राप्त सभी पांचो फेडरेशन ने एकमत से निर्णय लेकर डॉ. बिबेक देबरॉय समिति द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशों को सिरे से नकार दिया है. यह निर्णय 26 अप्रैल को एस्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के कार्यालय में हुई पांचो मान्यताप्राप्त फेडरेशनों की एक बैठक में लिया गया है. इन पांच फेडरेशनों में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ), नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), ऑल इंडिया रेलवे सुरक्षा बल संगठन (एआईआरपीएफए), फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशंस (एफआरओए) और इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओए) शामिल थे.

बैठक में देबरॉय समिति की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा सिलसिलेवार विचार-विमर्श किया गया. बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि देबरॉय समिति की सभी सिफारिशों को सिरे से नकारते हुए गुरूवार, 30 अप्रैल को पांचों फेडरेशनों द्वारा देबरॉय समिति के समक्ष एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसके अलावा इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी फेडरेशनों द्वारा देबरॉय समिति की अंतरिम सिफारिशों को खारिज करने वाले अपने अलग-अलग ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे. उल्लेखनीय है कि देबरॉय समिति ने अपनी अंतरिम सिफारिशों पर सभी सम्बंधित रेलवे श्रम संगठनों से 30 अप्रैल तक उनके विचार आमंत्रित किए हैं. इस महत्वपूर्ण बैठक में एआईआरएफ के अध्यक्ष कॉम. राखाल दासगुप्ता, महामंत्री कॉम. शिवगोपाल मिश्रा, एनएफआईआर के अध्यक्ष श्री गुमान सिंह, महामंत्री श्री एम. राघवैया, एआईआरपीएफए के अध्यक्ष श्री एस/ आर. रेड्डी, महामंत्री श्री यू. एस. झा, एफआरओए के अध्यक्ष श्री आर. आर. प्रसाद और आईआरपीओए के महामंत्री श्री रमन कुमार शर्मा उपस्थित थे.

आईआरसीटीसी 50 बड़े स्टेशनों पर बनाएगा सर्व-सुविधायुक्त प्रतीक्षालय

दिल्ली : पचास बड़े रेलवे स्टेशनों पर अपनी गाड़ियों के आने का इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए सर्व-सुविधायुक्त प्रतीक्षालय बनाए जाने की योजना है. इन आलीशान वातानुकूलित प्रतीक्षालयों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईआरसीटीसी ऐसे 50 बड़े और अति-व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्व-सुविधायुक्त प्रतीक्षालय बनाने की तैयारी में है. इसके लिए निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं. आईआरसीटीसी द्वारा इन आलीशान वातानुकूलित प्रतीक्षालयों में बैठने के लिए सोफा, टेबल, खाना, पत्र-पत्रिकाएं, टीवी, वाई-फाई कनेक्टिविटी, सामान रखने के लिए रेक और साफ-सुथरे शौचालय और बाथरूम आदि कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसका मकसद अपनी ट्रेनों के इंतजार में कश्मकश से गुजरते यात्रियों को सुखद अनुभव प्रदान करना है. लेकिन, इन सुविधाओं के लिए यात्रियों को भुगतान करना होगा. नई दिल्ली स्टेशन पर प्रयोग के तौर पर पहले से ही ऐसा एक सर्व-सुविधायुक्त प्रतीक्षालय कार्यरत है. इसके अलावा मुंबई, हावड़ा, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी सहित 50 अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों को इस प्रकार की सुविधाओं के लिए चिन्हित किया गया है. इस बीच आईआरसीटीसी 1,200 स्टेशनों पर 4,500 पानी बेचने वाली मशीनें लगाने की तैयारी कर रहा है. ऐसी प्रत्येक मशीन में एक ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम होगा, जिससे यात्रियों को अत्यंत कम कीमत पर साफ और ठंडा पानी उपलब्ध हो सकेगा. आईआरसीटीसी की इस पहल से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि अधिकतर मशीनों पर आदमी तैनात किए जाएंगे.

आईआरसीटीसी ने भूकंप पीड़ितों को भेजा 4 लाख लीटर रेलनीर

आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय के निर्देश पर नेपाल में आए भीषण भूकंप के कारण बेघर हुए नेपाली नागरिकों के लिए 25 अप्रैल को 50 हजार लीटर रेलनीर भेजा है. इसके तुरंत बाद 3.50 लाख लीटर पानी और भेजा गया है. इसके पहले भी आईआरसीटीसी ने जम्मू एवं कश्मीर में सितंबर 2014 में 4 लाख लीटर और अप्रैल 2015 में 70 हजार लीटर पानी भेजा था.

मेंबर इंजीनियरिंग की जीएम/उ.म.रे. के साथ अर्धकुम्भ की तैयारियों पर समीक्षा बैठक

उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय सूबेदारगंज, इलाहाबाद में उ.म.रे. मुख्यालय एवं इलाहाबाद मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मेंबर इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड श्री वी. के. गुप्ता (बीच में). उनके बाएं हैं महाप्रबंधक/उ.म.रे. श्री महेश मंगल और दाएं प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री सतीश कुमार.

इलाहाबाद : मेंबर इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड वी. के. गुप्ता के निरीक्षण दौरे के अवसर पर सोमवार, 27 अप्रैल को उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय सूबेदारगंज में उ.म.रे. मुख्यालय एवं इलाहाबाद मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेंबर इंजीनियरिंग श्री गुप्ता ने इलाहाबाद स्टेशन के डीकंजेशन के लिए किए जा रहे उपायों एवं आगामी अर्द्ध कुम्भ के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया. इस अवसर पर उपस्थिति अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए मेंबर इंजीनियरिंग ने कहा कि उ.म.रे. के इलाहाबाद मंडल ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है, किन्तु समय के साथ-साथ चुनौतियां और भी बड़ी होती जा रही हैं, इसलिए विभाग द्वारा जब भी किसी प्रोजेक्ट की परिकल्पना की जाए, तो तत्कालीन परिस्थितियों के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उसको बनाया जाए.

श्री गुप्ता ने कहा कि डीकंजेशन समाप्त करने के लिए इलाहाबाद जंक्शन के नजदीकी स्टेशनों को टर्मिनल्स के रूप में विकसित करने का कार्य तीव्रगति से चलाया जा रहा है. नैनी स्टेशन पर दो अतिरिक्त प्लेटफार्म के सर्वे का कार्य, इलाहाबाद से सूबेदारगंज तक चौथी लाइन के सर्वे का कार्य किया जा चुका है. डीकंजेशन समाप्त करने की दिशा में तीन नए फ्लाईओवर फाफामऊ से इरादतगंज, कर्छना से इरादतगंज एवं छिवकी से इरादतगंज के सर्वे का कार्य किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि इन फ्लाईओवर के बनने से इलाहाबाद जंक्शन पर गाड़ियों के रिवर्सन में लगने वाले समय में बचत होगी एवं गाड़ियों को सही समयपालन के साथ चलाया जा सकेगा. इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न नई रेल लाइनों का निर्माण जमीन से लगभग पर आठ मीटर ऊंचाई पर किया जाना, जिससे भूमि अधिग्रहण के दौरान होने वाले विवादों से बचा जा सकेगा, जानवरों के रनओवर की घटनाएं नहीं होंगी, साथ ही उन रेल लाइनों पर समपार फाटकों की भी आवश्यकता नहीं होगी, जैसे विभिन्न उपायों और सुझावों पर चर्चा की. इस अवसर पर पावर प्वांट प्रजेन्टेशन के माध्यम से महाप्रबंधक/उ.रे.म. महेश मंगल ने इलाहाबाद स्टेशन के डीकंजेशन एवं आगामी अर्द्ध कुम्भ के लिए की जा रही तैयारियों से अवगत कराते हुए मेंबर इंजीनियरिंग वी. के. गुप्ता से आग्रह किया कि रेलवे बोर्ड स्तर पर वे उत्तर मध्य रेलवे की हर सम्भव सहायता करने का प्रयास करें. बैठक में प्रमुख मुख्य इंजीनियर सतीश कुमार, मंडल रेल प्रबंधक, इलाहाबाद वी. के. त्रिपाठी, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक विजयी राम, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी बिजय कुमार सहित मुख्यालय के सभी विभाग प्रमुख एवं मंडल के सभी अधिकारीगण उपस्थित थे.

महाप्रबंधक/उ.म.रे. के साथ यांत्रिक अधिकारियों की बैठक

इलाहाबाद : उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, सूबेदारगंज में 28 अप्रैल को यांत्रिक विभाग के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई. इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक महेश मंगल ने अपने सम्बोधन में उत्तर मध्य रेलवे में यांत्रिक विभाग को लगातार दूसरे वर्ष रेल मंत्रालय द्वारा 'बेस्ट परफार्मेंस शील्ड' प्राप्त होने पर बधाई दी. उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने कार्य क्षेत्र और कार्यप्रणाली में लगातार सुधार करने, कार्यप्रणाली की कमियां खोजने, कैरिज एवं वैगन, डीजल इंजनों की गुणवत्ता में विश्वसनीयता को बनाने के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव और निर्देश दिए.

महाप्रबंधक श्री मंगल ने रेलवे के उपयोगकर्ता का विशेष ध्यान रखने हेतु लिनन तथा सवारी गाड़ियों की सफाई की गुणवत्ता को चाक-चौबंद रखने की आवश्यकता जताई. उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेनों की सफाई हेतु ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस में शामिल किया जाए तथा कोचों में डस्टबिन लगाए जाएं. इसके अतिरिक्त उन्होंने टॉयलेट को सुधारने एवं बायो टॉयलेट की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया और अधिक से अधिक आईएसओ प्रमाणित ट्रेन चलाने की बात भी कही. कर्मचारियों को सतर्क एवं दक्ष करके मालगाड़ियों में हॉट एक्सेल मामलों की संख्या कम करने और रेलवे में किसी भी परिस्थिति में संरक्षा से समझौता नहीं करने का भी निर्देश दिया.

बैठक में मुख्य यांत्रिक अभियंता ए. के. गुप्ता ने उत्तर मध्य रेलवे के सभी मंडलों, कारखानों से आए यांत्रिक अधिकारियों तथा मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों से निर्धारित लक्ष्यों तथा उनके निष्पादन का जायजा लिया. श्री गुप्ता ने इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे में यांत्रिक विभाग को लगातार दूसरे वर्ष रेल मंत्रालय द्वारा बेस्ट परफार्मेंस शील्ड प्राप्त होने पर बधाई दी और विभाग द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों का ब्यौरा देते हुए अधिकारियों को सम्बोधित किया. बैठक के दौरान उत्तर मध्य रेलवे के मंडलों एवं कारखानों से आए यांत्रिक अधिकारियों ने कम्प्यूटर के माध्यम से अपने-अपने कार्यों का प्रस्तुतीकरण किए. कांकोर द्वारा भी अपने विभाग का प्रस्तुतीकरण किया गया. इस अवसर पर पूर्व में जारी किए गए एजेंडा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा हुई. यांत्रिक विभाग द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर 2014-15 में उपलब्धियों एवं 2015-16 के लिए लक्ष्य के निर्धारण के लिए भी चर्चा हुई. इस बैठक में सभी विभाग प्रमुखों ने उत्तर मध्य रेलवे यांत्रिक विभाग के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

इलाहाबाद मंडल में 10.75 करोड़ की बिजली बची

इलाहाबाद : उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद मंडल अपनी कार्य-प्रणाली को बेहतर सुचारू एवं लागत प्रभावी बनाने के लिए मंडल रेल प्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में निरन्तर प्रयासरत है. इलाहाबाद मंडल ने अपने बिजली बिल के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रयास किए हैं. इन्हीं प्रयासों में इलाहाबाद मंडल ने 100 मेगावाट ट्रैक्शन पावर सप्लाई के लिए नेशनल थर्मल पावर कमीशन के साथ एक समझौता किया है. इसके लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ 50 मेगावाट का भी एक अल्प अवधि समझौता किया गया. इलाहाबाद मंडल के इस प्रयास से मार्च 2015 में ही दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ किए गए समझौते से 10.75 करोड़ रुपए के बिजली बिल में बचत हुई है. इलाहाबाद मंडल के विद्युत विभाग के इस प्रयास की उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और मुख्य विद्युत अभियंता द्वारा भी सराहना की गई है.

नई दिल्ली यार्ड में सियालदह और भुवनेश्वर राजधानी के 6 कोच जलकर खाक

नई दिल्ली. स्टेशन यार्ड की कोच वाशिंग पिट लाइन में मंगलवार, 21 अप्रैल को दोपहर बाद लगी भयंकर आग से सियालदह राजधानी के 4 और भुवनेश्वर राजधानी के 2 (कुल 6) कोच जलकर खाक हो गए. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, मगर आग बुझाने के प्रयास में आरपीएफ सहित कई रेलकर्मियों के हाथ झुलस गए हैं. आरपीएफ और दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद करीब चार घंटे में आग पर काबू पाया जा सका. तथापि, दोनों राजधानियों के 6 कोचों को भष्म होने से नहीं बचाया जा सका. इसके अलावा सियालदह राजधानी का एक और कोच कुछ जल गया है. हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है, मगर यह आग सियालदह राजधानी के चार में से किसी एक कोच में शार्ट सर्किट से लगे होने की आशंका आरपीएफ कर्मियों ने जताई है. इस आग पर यदि वक्त रहते काबू नहीं पा लिया गया होता, तो वहीं यार्ड से होकर गुजरी डीजल पाइप लाइन के भी जलकर फूट जाने की आशंका पैदा हो गई थी. तथापि, इस आग से इस पाइप के एक मुहाने पर लगा प्लास्टिक का ढक्कन पिघल चुका था. यदि यह डीजल पाइप आग पकड़ ली होती, तो कुछ ही दूरी पर स्थित डीजल डिपो में होने वाले भयंकर विस्फोट को नहीं बचाया जा सकता था. इससे होने वाली हानि का तो फिलहाल अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है. इसके अलावा दोनों राजधानियों में लगी जनरेटर कार तक भी आग नहीं पहुंच पाई थी. वरना इन जनरेटर कारों से भी भयंकर विस्फोट हो सकता था. जो कि पहले भी चलती गाड़ियों में कई बार आग लगने का कारण बन चुकी हैं. बहरहाल रेल प्रशासन ने इस आग हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं. मगर आब तक किसी के प्रति इसकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है.

सरकारी कर्मचारियों को प्रीमियम ट्रेनों...

पेज 1 से आगे... सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही की जा सकती है. यह आदेश उन सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू किया गया है, जो ऑन ड्यूटी कार्यालयीन कामकाज से कहीं जा रहे होंगे अथवा प्रशिक्षण या तबादले पर जा रहे हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा प्रीमियम ट्रेन में पहले ही यात्रा कर ली गई है, तो उसे सम्बंधित श्रेणी, जिसमें उसने यात्रा की है, तो उस श्रेणी का उस दिन का सामान्य कराया अथवा उस दिन के प्रीमियम किराया, जो भी कम होगा, उसे भुगतान करना होगा. ज्ञातव्य है कि रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने हाल ही में एक टास्क फोर्स का गठन करके प्रीमियम पालिसी का विस्तार करते हुए इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू किए जाने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया है.

हमारा विशेष ध्यान यात्री सुविधाओं में निरंतर सुधार पर है -राजीव मिश्र

गोरखपुर : रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर 19 अप्रैल को गोरखपुर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने विभिन्न विभागों के 204 रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति-पत्र, गोल्ड मेडल एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया, जिनकी उत्कृष्ट एवं समर्पित सेवाओं से रेल की कार्य-प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, उत्पादकता बढ़ी है, रेल दुर्घटनाएं बचाई जा सकी हैं तथा तकनीकी सूझबूझ से आर्थिक नुकसान को बचाया जा सका है.

60वें रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर आयोजित रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र एवं पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती कुमकुम मिश्रा.

पू.रे., लखनऊ मंडल द्वारा वर्ष 2014-15 में सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए महाप्रबंधक की समग्र कार्यकुशलता शील्ड प्रदान की गई. महाप्रबंधक श्री राजीव मिश्र से शील्ड ग्रहण करते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री अनूप कुमार.

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने पुरस्कृत होने वाले सभी रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी के सामूहिक प्रयास से गत वर्ष पूर्वोत्तर रेलवे का सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा है और इस वजह से पूर्वोत्तर रेलवे ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं. महाप्रबंधक ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की विशेष कार्यशैली से रेलवे की कार्य-प्रणाली में सुधार होने के साथ ही उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है तथा कई रेल दुर्घटनाएं बचाई जा सकी हैं. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे की रेल परिवहन में संरक्षा, यात्री एवं रेल सम्पत्ति की सुरक्षा, गाड़ियों का समय-पालन, बेहतर यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करना, परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना एवं गाड़ियों तथा स्टेशनों की स्तरीय साफ-सफाई आदि सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं.

महाप्रबंधक श्री मिश्र ने कहा कि मुख्यतः यात्री प्रधान रेलवे होने के कारण, साफ-सफाई पहले से ही हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रही है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियों की संरक्षा, सुरक्षा एवं समय-पालन में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि मुख्य रेलपथ बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा का दोहरीकरण पूरा हो चुका है. इस खंड के विद्युतीकरण का कार्य अंतिम चरण में है. इसके साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे में आमान परिवर्तन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है. महाप्रबंधक ने बताया कि इस वर्ष के रेल बजट में पूर्वोत्तर रेलवे को नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण तथा यात्री सुविधाओं हेतु पर्याप्त निधि का आवंटन किया गया है. इसके फलस्वरूप आगामी तीन-चार वर्षों में पूर्वोत्तर रेलवे को भारतीय रेल के महत्वपूर्ण रेल सिस्टम के रूप में स्थापित होने में सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि हमारा विशेष ध्यान यात्री सुविधाओं में निरंतर सुधार पर है.

निर्माण परियोजनाओं के अंतर्गत कासगंज-बरेली-लालकुंआ आमान परिवर्तन के तहत रामगंगा ब्रिज-कासगंज रेल लाइन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इसी प्रकार गोरखपुर-आनंदनगर-गोंडा (लूप) आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत बढ़नी-गोंडा खंड का आमान परिवर्तन भी जून, 2015 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है. लखनऊ-सीतापुर-मैलानी-पीलीभीत खंड का आमान परिवर्तन आरवीएनएल द्वारा किया जा रहा है. छपरा-थावे मीटर गेज खंड का आमान परिवर्तन कार्य 1 अप्रैल, 2015 से शुरू कर दिया गया है. जबकि भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर तथा गोंडा-बहराइच रेल खंडों के आमान परिवर्तन को भी जल्दी ही पूरा करने की योजना है. दोहरीकरण के अंतर्गत चालू वर्ष 2015-16 में इलाहाबाद-मंडुवाडीह तथा गाजीपुर-बलिया रेल खंडों की स्वीकृति मिलने के साथ ही अब इलाहाबाद-मंडुवाडीह-छपरा तक पूरे रेल खंड का दोहरीकरण, विद्युतीकरण के साथ स्वीकृत हो गया है.

निजी सार्वजनिक भागीदारी में रेलवे...

पेज 1 से आगे... है. बताते हैं कि यहां से होने वाली कोल लोडिंग माल वैगनों में उनकी क्षमता से ज्यादा और वैगन की ऊंचाई से ऊपर तक की जाती है, जिससे मालगाड़ी के तेज गत से चलने पर वैगन से ऊपर तक भरा कोयला तेज हवा से उड़कर रेल लाइन के किनारे काम करने वाले गैंगमैनों, गेटमैनों और प्लेटफार्म पर खड़े रेल यात्रियों पर गिरता है, जिससे उन्हें चोट पहुंच रही है, जबकि इस उड़कर पड़ने वाले कोयले से कई लोगों की आंख भी खराब हो चुकी है. इसी वेबसाइट www.rail-samachar. com पर एक प्लेटफार्म से गुजर रही कोयले से ओवरलोडेड मालगाड़ी को देखा जा सकता है, जिसमें वैगन से काफी ऊपर तक लोड किए गए कोयले की स्थिति से इस उपरोक्त बात की पूरी तरह से पुष्टि हो रही है. बताते हैं कि कोयें से ओवर लोडेड यह मालगाड़ी ट्राम्बे से लोड होकर निकली है.

देश के सभी श्रमिक संगठनों का संसद पर प्रचंड प्रदर्शन...

पेज 1 से आगे... इसके अलावा कुछ राज्यों के कर्मचारी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए. कॉम. मिश्रा ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की लंबित मांगों को उठाया गया, जिनमें मुख्य रूप से नई पेंशन योजना को समाप्त करना, महंगाई भत्ते को वेतन में विलय करना, छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को समाप्त करना, अंतरिम राहत देना, एफडीआई और पीपीपी को समाप्त करना, खाली पड़े लाखों पदों को तत्काल भरना, आउटसोर्सिंग को बंद करना, बोनस की सीमा राशि को बढ़ाना और श्रम कानूनों में बदलाव आदि प्रमुख हैं. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार हमारे इस संयुक्त आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेती है, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा.

कॉम. मिश्रा ने यह भी कहा कि हमें और लाखों रेलकर्मियों को ऊपर वाले प्रभु के साथ-साथ नीचे वाले सुरेश प्रभु पर भी पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण करके रेलवे को कुछ ऐसे औद्योगिक घरानों को सौंप देना चाहती है, जो सरकार को चुनावों में मोटी-मोटी राशि का चंदा देते हैं अथवा ऐसे घराने जो अपने निहित स्वार्थ के चलते रेलवे के 13.50 लाख रेलकर्मियों के हक पर डाका डालने की फिराक में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि मैं तो ऊपर वाले प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलमंत्री सुरेश प्रभु को सद्बुद्धि दे.

कॉम. शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि देश की करीब 98 प्रतिशत आबादी आज रेलवे से यात्रा करती है और रोजाना लगभग तीन करोड़ लोग रेलवे से सफर कर रहे हैं, मगर देश का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यह सरकार निजी वाहनों या हवाई जहाज से यात्रा करने वाली मात्र दो प्रतिशत साधन सम्पन्न आबादी के हितों के बारे में ही सोच रही है. देश की सबसे सस्ती, सुलभ और सुरक्षित यातायात प्रणाली रेलवे ही है. उनका कहना था कि केंद्र सरकार और देश की कुछ राज्य सरकारें नहीं चाहती हैं कि रेलवे का विस्तार हो. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि रेलवे को निजी हाथों में सौंपकर लोगों से मनमाना किराया वसूला जाए. जबकि कुछ राज्य सरकारें चाहती हैं कि रेलवे निजी हाथों में चली जाए, तो वह और उनके मंत्री रेलवे को अपनी निजी जागीर बना लें, मगर रेलवे के लाखों रेलकर्मी उनके इन मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देंगे.

23 नवंबर से राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय

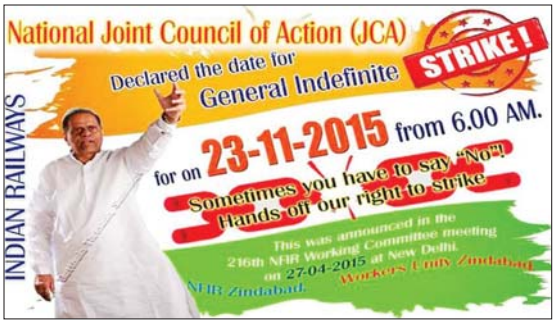

28 अप्रैल के संसद पर विशाल प्रदर्शन और घेराव के दौरान एआईआरएफ के महामंत्री और राष्ट्रीय संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक कॉम. शिवगोपाल मिश्रा ने बताया कि सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में आगामी 23 नवंबर 2015 को सुबह 6 बजे से रेलवे सहित सभी केंद्रीय कर्मचारियों की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का निर्णय भी लिया गया. प्रस्ताव में कहा गया है कि महीनों पहले सरकार को सौंपे 10 सूत्री चार्टर ऑफ डिमांड को यदि इस बीच सरकार ने स्वीकार नहीं किया, तो 23 नवंबर से सभी केंद्रीय कर्मचारी सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इस दरम्यान रेलवे और रक्षा क्षेत्र के संगठन औद्योगिक विवाद कानून एवं मान्यता नियमों के तहत हड़ताल पर जाने के निर्णय पर एक बार फिर से गुप्त मतदान करवाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और रेलमंत्री द्वारा विभिन्न मंचों सहित संसद में भी बार-बार यह कहा गया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा. इसके बावजूद डॉ. बिबेक देबरॉय समिति की अंतरिम रिपोर्ट रेलवे के सम्पूर्ण निजीकरण की तरफ इशारा कर रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर जेसीएम को बंद कर दिया है, जो कि सन 1966 से केंद्रीय कर्मचारियों के हितों की सफलतापूर्वक देखभाल करती आ रही थी. उन्होंने कहा कि 25 फरवरी 2015 को कार्मिक सचिव के साथ हुई बैठक के बाद से आज तक कर्मचारियों की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है. यह सरकार चालबाजी से कर्मचारियों की आंखों में जो धूल झोंकने का प्रयास कर रही है, उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने ही कर्मचारियों से कोई टकराव नहीं चाहती है तो उसे एनसी-जेसीएम की बैठक तुरंत बुलाकर उनकी मांगों पर फौरन कोई निर्णय ले लेना चाहिए.

एआईआरटीसीएसओ ने भी 28 अप्रैल के प्रदर्शन में दर्ज कराई उपस्थिति

नई दिल्ली. ऑल इंडिया रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन (एआईआरटी सीएसओ) ने भी 28 अप्रैल को दिल्ली में हुए प्रदर्शन में रेलवे की मान्यताप्राप्त फेडरेशनों के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी मांगों के लिए रेलवे की दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशनों को अपना समर्थन दिया. यह जानकारी देते हुए एआईआरटीसीएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुकेश गौतम ने 'रेलवे समाचार' को बताया कि यही सबसे उपयुक्त मौका था, जब एआईआरटीसीएसओ अपनी मजबूत यत्किंचित सहयोग और समर्थन दे सकता था.

डॉ. गौतम ने बताया कि एआईआर टीसीएसओ ने अन्य विभागों से मेडिकली अनफिट और डिकैटेगराइज रेलकर्मियों को वाणिज्य विभाग और खासतौर पर टिकट चेकिंग ब्रांच में पदस्थ किए जाने के खिलाफ अब अपना खुला विरोध जताया है. इसी विषय पर 8 अप्रैल को सभी जोनल और मंडल मुख्यालयों में जीएम एवं डीआरएम को टिकट चेकिंग स्टाफ ने एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में कहा गया है कि रेल प्रशासन द्वारा अन्य विभागों से मेडिकली अनफिट और डिकैटेगराइज रेलकर्मियों को वाणिज्य विभाग में पदस्थ किए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह कतई उचित नहीं है. इससे टिकट जांच सहित सभी वाणिज्य कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है. इस प्रस्ताव को अविलंब वापस लिए जाने की मांग की गई है.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा एआईआरटीसीएसओ की तरफ से देश भर के टीटीई रेस्ट हाउसेस की दशा सुधारे जाने की मुहिम चलाई जा रही है. अब तक देश भर के करीब 50 टीटीई रेस्ट हाउस का कायाकल्प शुरू हो चुका है, जिनकी तरफ पिछले 50 साल से रेल प्रशासन का कोई ध्यान नहीं था. इसके साथ है संगठन ने सभी जोनों में जोनल संगठनों के पदाधिकारियों की नियुक्ति करके वहां एजीएम करवाई है और कोंकण रेलवे में भी संगठन का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि आज टिकट चेकिंग स्टाफ नई तकनीक से लैस होकर पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से एक-दूसरे से लगातार संपर्क में बना हुआ है. अब रेल प्रशासन और मायाताप्राप्त रेल संगठन भी टिकट चेकिंग स्टाफ को तवज्जो देने लगे हैं. यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

उन्होंने कहा कि सन 1974 के बाद से अब तक रेलकर्मियों ने एक घंटे की भी हड़ताल नहीं की है. लेकिन आज 41 साल बाद फिर से वही हालात बन गए हैं कि न चाहते हुए भी रेलवे के 13.50 लाख रेलकर्मियों को हड़ताल पर जाने का निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ा है. उन्होंने कहा कि आज संसद पर प्रदर्शन और घेराव का फैसला किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि देश के 96.6 प्रतिशत रेलकर्मियों का सामूहिक फैसला है. उन्होंने कहा कि कई महीनों से सरकार के समक्ष रेलकर्मियों की 34 मांगें रखी गई थीं, मगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है. आज सरकार को देश के करोड़ों मजदूरों की ताकत का बखूबी अंदाजा हो गया होगा. उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन और घेराव में देश भर से करीब 10 लाख मजदूर शामिल हुए हैं.

रेलवे देश के विकास और परिवहन का महत्वपूर्ण साधन...

पेज 1 से आगे... जोर दिया, जिसकी वजह से रेलवे की आर्थिक हालत ख़राब हो गई है. रेलमंत्री ने कहा कि आगामी पांच वर्षों में बहुत सोच-विचार के साथ रेलवे में निवेश करने सहित इसकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 2000 किमी. रेल लाइन के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें रेलवे के साथ मिलकर रेल परियोजनाओं पर काम करें, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है. रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे देश के विकास और परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है. रेलवे के विकास से देश का विकास जुड़ा है. उन्होंने कहा कि भविष्य में देश की विकास दर को बढ़ाकर 10 से 12 प्रतिशत तक पहुंचाना भी महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेगा. इस अवसर पर रेलमंत्री ने यह भी घोषणा की कि हरियाणा में निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के तहत रेल कोच फैक्टरी लगाई जाएगी. इसके अलावा हरियाणा और रेलवे के बीच स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के अंतर्गत शीघ्र ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए अध्ययन करेगी और उन परियोजनाओं पर अमल करने की सरल सिफारिशें देगी.

इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रोहतक-भटिंडा-लहरा मोहब्बत रेल लाइन के विद्युतीकरण से दो राज्यों के बीच रेल की तीव्र गति, सुगम परिचालन, एमईएमयू सेवाओं की शुरूआत और यात्रा के अनुकूल पर्यावरण सहित कई फायदे होंगे. उन्होंने हरियाणा की रेल परियोजनाओं पर सकारात्मक पहल पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि एसपीवी के गठन के बाद हरियाणा की प्रस्तावित रेल परियोजनाओं को गति मिलेगी. मुख्यमंत्री ने करनाल-यमुनानगर, फतेहाबाद-मानसा, फिरोजपुर-झिरका-अलवर, हिसार-सिरसा वाया अग्रोहा सहित अन्य कई नई लाइनों की मांग के साथ जींद-सोनीपत रेल लाइन का काम जल्दी पूरा करने की मांग भी रखी. उन्होंने प्रदेश के 119 मानवरहित रेलवे फाटकों को सुरक्षित करने की बात पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि या तो यह फाटक बंद किए जाएं अन्यथा यहां फाटक की व्यवस्था करने के साथ-साथ भूमिगत अथवा पैदल ऊपरी पुल बनाने पर भी विचार होना चाहिए, ताकि यहां होने वाले हादसों पर अंकुश लग सके. उन्होंने कहा कि गुड़गांव रेलवे स्टेशन को भी सीएसआर की मदद के साथ आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है. इसके जवाब में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने मुख्यमंत्री की मांग के अनुरूप रोहतक के अंदर से निकल रही रेल लाइन को भूमिगत अथवा मेट्रो की तर्ज पर शहर से बाहर करने के विकल्प की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए रेल अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए. उन्होंने रोहतक रेलवे स्टेशन को आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने और भिवानी से हरिद्वार के बीच ट्रेन चलाने की मांग को भी पूरा करने का आश्वासन दिया. इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सांसद शादी लाल बत्रा, विधायक मनीष कुमार ग्रोवर, मेंबर इलैक्ट्रिकल, रेलवे बोर्ड, नवीन टंडन, महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, ए. के. पुठिया, महाप्रबंधक, केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन एवं उत्तर मध्य रेलवे, महेश मंगल, दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अरूण अरोड़ा एवं अनेक वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित थे.

उल्लेखनीय है कि 252 रूट किमी. और 580 ट्रैक किमी. की इस परियोजना को 294 करोड़ रुपये की लागत पर एवं 14.02 प्रतिशत की वित्तीय और आर्थिक वापसी दर पर 12वीं योजना में 21 जनवरी, 2010 को शामिल किया गया था. रोहतक से बटिंडा (227 रूट किमी.) दोहरी लाइन और बटिंडा-लहरामोहब्बत (25 रूट किमी.) एकहरी लाइन वाला सेक्शन है. इस समूचे सेक्शन पर 33 रेलवे स्टेशन हैं.

विद्युतीकरण कार्य के अन्तर्गत ओएचई उपकरणों का प्रावधान, स्विचिंग स्टेशन पोस्ट (14) का निर्माण, पर्यवेक्षी रिमोट कंट्रोल और डाटा अर्जन प्रणाली, ग्रिड सब-स्टेशन (4), टांसमिशन लाइनें, सिविल इंजीनियरिंग तारें, सिगनलिंग प्रणाली एवं स्टेशनों की पैनल इंटरलाकिंग प्रणाली को सुधारना, 25 किलोवाट कर्षण प्रणाली के अनुकूल रंगीन रोशनी वाले सिगनल और दूरसंचार प्रणाली में सुधार, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, डाटा लॉगर, एलईडी सिगनल और ब?लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर शामिल हैं. इस सेक्शन की अप लाइन पर 2 डिग्री तथा डाउन लाइन पर 0.5 डिग्री वाले तीखे मोड हैं और इसका रूलिंग ग्रेडियंट 500 में 1 है. इस लाइन पर 179 समपार फाटक और 24 पुल/रोड ओवर/अंडर ब्रिज हैं. इस प्रणाली को 4 डिग्री से 60 डिग्री सैल्सियस तापमान के अनुकूल रहने के लिए डिजाइन किया जा रहा है. यह रेल मार्ग छोटा नागपुर/मध्य प्रदेश की कोयला खदानों से राजस्थान तक कोयला यातायात की ढुलाई करता है. इसके अलावा पंजाब के विभिन्न उद्योगों और खट्टर सिंह वाला तथा लहरामोहब्बत में स्थित थर्मल पावर स्टेशनों को भी कोयले की आपूर्ति करता है. यह सेक्शन नापथा, चूना पत्थर, सीमेंट, एलपीजी, कोटा स्टोन, टीकवुड इत्यादि कच्चे माल की ढुलाई में भी इस्तेमाल होता है. वर्तमान में लहरामोहब्बत से/तक प्रतिदिन 3-4 रैकों का आवागमन होता है. इसके अलावा खट्टर सिंह वाला और लहरामोहब्बत थर्मल पावर स्टेशनों की क्षमता भी बढ़ रही है, जिससे भविष्य में यहां यातायात में और भी वृद्धि होगी. दिल्ली से मुम्बई को जोड़ने वाली मुख्य लाइन पर विद्युतीकरण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है. दिल्ली क्षेत्र के विद्युतीकरण के पश्चात छोटा नागपुर और दक्षिण की कोयला खानों से समूचा यातायात विद्युत कर्षण द्वारा शकूरबस्ती आ रहा है. शकूरबस्ती में विद्युत से डीजल और डीजल से विद्युत कर्षण परिवर्तन के चलते सीधे जाने वाली रेलगाड़ियों के परिचालन पर असर पड़ता है. दिल्ली-अम्बाला-कालका रेल सेक्शन की क्षमता का उपयोग वर्ष 2006-07 में 140 प्रतिशत था और मालभाड़ा यातायात में इस सेक्शन की सालाना वृद्धि 10 प्रतिशत थी. अतः यह सम्भव नहीं था कि ढुलाई का कार्य दिल्ली-अम्बाला-कालका सेक्शन से होकर किया जाए. इस सेक्शन के विद्युतीकरण से दिल्ली/हरियाणा राज्य विशेषकर दिल्ली-रोहतक सेक्शन से आने वाले दैनिक यात्रियों को भी सुविधा होगी. इस सेक्शन पर ईएमयू/एमईएमयू सेवाओं से रेलयात्री लाभान्वित होंगे. इस परियोजना के विद्युतीकरण से सुगम आवागमन, चल स्टॉक एवं इंजनों की समय पर वापसी, सेक्शन की उच्चतर क्षमता, उन्नत पर्यावरण, बेहतर संरक्षा, उन्नत ऊर्जा दक्षता एवं मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के यात्रा समय में 90-120 मिनट की कमी आएगी, जिससे उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618 प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित ■ POST Regd. No. THC/135/2015-2017

आखिर आनंद विहार-लखनऊ एसी सुपरफास्ट डबल डेकर गाड़ी को मिली हरी झंडी

दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 26 अप्रैल को आनंद विहार टर्मिनल एवं लखनऊ जंक्शन के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली वातानुकूलित डबल डेकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी सं. 12584/12583 को आनंद विहार टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने की. इस अवसर पर रेल राज्यपंत्री मनोज सिन्हा, सांसद महेश गिरी, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे ए. के. पुठिया एवं मंडल रेल प्रबंधक अरुण अरोरा सहित रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.

इस अवसर पर बोलते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ एवं दिल्ली के बीच इस सुविधाजनक डबल डेकर ट्रेन की सेवा शुरू करने के लिए रेलवे की सराहना की. उन्होंने रेलमंत्री से सप्ताह में दो दिन चलाई जाने वाली इस नई गाड़ी को दैनिक आधार पर चलाने का अनुरोध किया तथा आनंद विहार टर्मिनल के स्थान पर इसे नई दिल्ली स्टेशन से चलाए जाने की संभावना पर भी विचार करने को कहा.

आनंद विहार टर्मिनल - लखनऊ जं. वातानुकूलित सुपरफास्ट द्वि-साप्ताहिक डबल डेकर एक्सप्रेस रेलगाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रेल राज्यपंत्री मनोज सिन्हा एवं अन्य.

अपने संबोधन में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे के समक्ष डबल डेकर गाड़ी के कोच को रेलवे नेटवर्क के अनुरूप अर्थात आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और भार आदि को रेल पुलों, विद्युत लाइनों, टनल, प्लेटफार्म आदि के अनुकूल बनाने की चुनौती थी. इस चुनौती को रेलवे द्वारा डबल डेकर कोच के डिजाइन में मामूली परिवर्तन कर अन्य शताब्दी कोच में उपलब्ध 78 सीट की तुलना में 120 यात्रियों के बैठने की क्षमता उपलब्ध कराई गई है.

उन्होंने कहा कि डबल डेकर कोच का निर्माण भी रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. यह कोच स्टेनलेस स्टील से निर्मित होने के कारण इनका भार भी अपेक्षाकृत कम है. संरक्षा की दृष्टि से भी इन डिब्बों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है, ताकि वे किसी विपरीत स्थिति में एक-दूसरे पर न चढ़ें. उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने डबल डेकर कोच निर्मित कर यात्रियों को न्यूनतम दरों पर अधिक सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दर्शाई है. इसके लिए उन्होंने रेलकर्मियों की प्रशंसा की ओर उन्हें बधाई भी दी.

यात्रियों की सुरक्षा एवं सुख-सुविधा संबंधी हेल्पलाइन नंबर

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सभी जोनल रेलों ने यात्रियों की सुरक्षा एवं सुख-सुविधा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर यात्री इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके इनका आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकें. रेलवे के हेल्पलाइन नंबरों का विवरण इस प्रकार है..

1. यात्रियों की सुरक्षा संबंधी समस्याएं - 182
2. यात्रियों की अन्य समस्या संबंधी 138
3. यात्रियों की पूछताछ संबंधी 139

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि उक्त सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं से रेल प्रशासन को फौरन अवगत करवाएं.

सीनियर डीएसटीई/को. मुंबई मंडल, म.रे. जनार्दन सिंह महाप्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित

60 वें रेल सप्ताह के अवसर पर उत्कृष्ट सेवाओं और तत्परतापूर्वक कार्य-निष्पादन के लिए मध्य रेलवे, मुंबई मंडल के वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता/समन्वय (सीनियर डीएसटीई/कोआर्डिनेशन) जनार्दन सिंह को महाप्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया. महाप्रबंधक सुनील कुमार सूद से प्रशस्ति पत्र, पदक और नकद पुरस्कार ग्रहण करते हुए जनार्दन सिंह.

एसीएम/कोटा के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर. एस. झा ने अपने एक अंतरिम आदेश में पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल में पदस्थ सहायक वाणिज्य प्रबंधक (एसीएम) सुनील कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ विभागीय एवं पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मामले से सम्बंधित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब-तलब भी किया है. फर्जी पुलिस उत्पीड़न के इस मामले में वादी एसीएम श्रीवास्तव ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है.

वकील अजय रायजादा ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल याचिकाकर्ता एसीएम श्रीवास्तव को जीआरपी कटनी द्वारा फर्जी मामले में फंसाने के लिए बुरी तरह परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसके पीछे रीवा रेंज के पूर्व आईजी का दबाव मुख्य कारण है. वस्तुस्थिति यह है कि याचिकाकर्ता चीफ लॉ असिस्टेंट रहने के समय रेलवे विजिलेंस में काम कर चुका है. उस दौरान उसने अपनी टीम के साथ रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया था. इस वजह से कठघरे में आए रेलवे अधिकारी उससे द्वेष भावना रखते हैं. अदालत में बहस के दौरान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक टीसी के खिलाफ शिकायत मिली थी. जिस पर छापा मारकर उसकी तलाशी ली गई. उसके पास 10 रुपए कम पाए गए. चूंकि शिकायत झूठी थी, अतः बिना कार्रवाई के उसे छोड़ दिया गया था. कुछ दिन बाद उसी टीसी को बरगलाकर जीआरपी कटनी में आरपीएफ और याचिकाकर्ता तत्कालीन विजिलेंस इंस्पेक्टर के खिलाफ प्रताड़ना का झूठा आरोप लगाकर फर्जी मामला दर्ज करा दिया गया. तथापि मामले की जांच के बाद रेलवे के उच्च अधिकारी क्लीनचिट दे चुके हैं, क्योंकि जिस दिन प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है, उस दिन याचिकाकर्ता स्वीकृत अवकाश पर था. हाईकोर्ट के निर्देश पर डीजीपी ने भी इस मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता को क्लीनचिट दी है. इसके बावजूद जीआरपी कटनी याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने की कोशिश में है. इसीलिए पुलिसिया उत्पीड़न से बचने हेतु याचिकाकर्ता को सीबीआई जांच कराए जाने की मांग के साथ हाईकोर्ट में मामला दाखिल करना पड़ा है.

शेयर बाजार के ट्रेक पर नहीं चल सकती है भारतीय रेल -सुरेश प्रभु

मुंबई : रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रही भारतीय रेल 'अस्तित्व के संकट' से गुजर रही है, लेकिन उन्होंने रेलवे के लिए पूंजी जुटाने के हेतु शेयर बाजार के रास्ते जाने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि सड़क क्षेत्र को लंबे समय तक काफी तरजीह दी गई है और रेलवे की उपेक्षा होती रही है. हालांकि, उन्होंने रेलवे के लिए पूंजी जुटाने के हेतु ओएनजीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनियों की तरह शेयर बाजार का रास्ता अपनाने से इनकार किया. श्री प्रभु ने कहा, 'सड़क क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता देने से रेलवे को यातायात का नुकसान हुआ, क्योंकि रेलवे के मुकाबले सड़कों में तीन से चार गुना अधिक निवेश किया गया. उन्होंने कहा कि सरकारों ने सड़क क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देकर रेलवे की उपेक्षा की है. उन्होंने कहा कि यदि सड़क के मुकाबले रेल यातायात बढ़ाना चाहते हैं, तो रेलवे में ज्यादा निवेश करना होगा.

रेलमंत्री से जब यह पूछा गया कि काफी प्रयासों के बावजूद रेलवे, सड़क मार्ग से माल ढुलाई को अपनी तरफ मोड़ने में विफल रही है, तो इस पर उनका कहना था कि हिस्सा बढ़ाने के लिए माल ढुलाई को अगर निशुल्क भी कर दिया जाए, तो भी रेलवे उसका प्रबंधन नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि रेलवे लोगों को मुफ्त माल ढुलाई की अनुमति

लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रही भारतीय रेल 'अस्तित्व के संकट' से गुजर रही है –रेलमंत्री

देने का निर्णय करती है, तो क्या रेलवे उसका प्रबंधन करने में सक्षम है? उन्होंने प्रति-प्रश्न करते हुए कहा कि रेलवे के पास माल ढुलाई की क्षमता ही कहां है? इसीलिए रेलवे में निवेश करना होगा.

रेलवे को ओएनजीसी समेत सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों की तरह धनराशि जुटाने के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की सलाह दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे की अपनी अलग विशिष्टता है और उसके लिए ऐसा करना उपयुक्त नहीं होगा. उन्होंने कहा कि रेलवे भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरह एक मंत्रालय है. जबकि ओएनजीसी स्वायत्त कॉर्पोरेट निकाय है. रेलवे सरकार का विभागीय उपक्रम है. इसीलिए हम इसके बारे में नहीं सोच सकते और इसके बारे में सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि रेलवे की अपनी अलग विशेषता है. उन्होंने कहा कि अगर रेलवे को विभागों में बांटा जाता है, तो भी इसकी उपयुक्त सूचीबद्धता नहीं हो पाएगी.

उन्होंने कहा कि हम रेलवे में एक विशेष लेखा प्रणाली पेश कर रहे हैं. यह लेखा प्रणाली उन बिंदुओं को चिन्हित करेगी, जिनका लाभ पब्लिक उठा रही है. प्रत्येक सेवा पर कितनी लागत है? रेलवे में हम अगर कोई व्यय कर रहे हैं, तो उसका इच्छित नतीजा निकल रहा है या नहीं और व्यय के लिए जिस समय-सीमा की आपने प्रतिबद्धता जताई है, उसका पालन हुआ कि नहीं, यह सब इस प्रणाली से निर्धारित होगा. कायाकल्प परिषद के बारे में पूछे जाने पर रेलमंत्री ने कहा कि इसकी अध्यक्षता रतन टाटा कर रहे हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक कारोबार किया है, उनके साथ हितों के टकराव की भी कोई समस्या नहीं है.

आजीवन सदस्यता 3000 रु.,
संरक्षक सदस्यता 5000 रु.,
कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार
रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. : 9869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक **सुरेश त्रिपाठी** द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर्स हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जिला- ठाणे. (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक – सुरेश त्रिपाठी

- इलाहाबाद : **उमेश शर्मा** ☎ 094155 08625
- गोरखपुर : **विजय शंकर** ☎ 094508 80000
- भुसावल : **शेख सत्तार** ☎ 093706 15244
- रतलाम : **मुकेश सिंह** ☎ 094274 84069
- वड़ोदरा : **विजय नायर** ☎ 098240 16464

कानूनी सलाहकार
एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण, एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई, एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे, एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली, एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल, एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.
किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017